वर्ष : 16 ❖ अंक : 183 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
शनिवार, 12 फरवरी 2022

परिवार वाला व्यक्ति झोला लेकर नहीं भागेगा : अखिलेश 3

विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी : पीएम मोदी 8

खेतीयोग्य क्षेत्र का विस्तार करें किसान : मंत्री शर्मा

अनुगामिनी नि.सं.

गेजिंग, 11 फरवरी । राज्य सरकार के कृषि विभाग ने आज गेजिंग बर्मेक निर्वाचन क्षेत्र के मार्तम में प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 274 लाभार्थियों को सिन्टेक्स तथा अन्य कृषि उपकरणों का वितरण किया।

लघु सिचाई सम्बन्धी सचेतना तथा उपकरण वितरण कार्यक्रम में कृषि तथा बागवानी विभाग के मन्त्री लोकनाथ शर्मा प्रमुख आतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके साथ पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवा विभाग के सहलाकार दुर्गा प्रसाद प्रधान, कृषि विभाग के सह निदेशक (पश्चिम) टीएन भूटिया, ही मार्तम खण्ड विकास अधिकारी प्रतिभा तमांग, एसकेएम पार्टी के पश्चिम जिला अध्यक्ष एबी लिम्बू प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

कृषि तथा बागवानी विभाग के मन्त्री लोकनाथ शर्मा ने रुंगदु बर्थांग, चिंगथांग, बेर्फोक, मियोंग, मिग्योंग और मार्तम के चिह्नित स्थानों के 274 लाभार्थी कृषकों को उपकरण प्रदान किया। प्रत्येक लाभार्थियों को एक हजार लीटर की क्षमता वाली पोली टंकी और अन्य माइक्रो सिचाई से संबंधित सामान वितरित किए गए।

उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत न्यूनतम 0.22 हेक्टेयर सब्जी की खेती और 0.4 हेक्टेयर इलाइची की खेती की जाती है। मन्त्री शर्मा ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को खेतीयोग्य क्षेत्र विस्तार करने का भी निवेदन किया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र के गेजिंग बजार का भ्रमण करते हुए स्थानीय व्यापारियों का हालचाल लिया। उन्होंने गेजिंग बाजार की आगामी योजनाओं को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी।

मंत्री शर्मा ने त्योंगसी सिजिजंगा उच्चतर माध्यमिक स्कूल का किया दौरा

अनुगामिनी नि.सं.

गेजिंग, 11 फरवरी । गेजिंग बर्मेक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तथा मंत्री लोकनाथ शर्मा ने आज त्योंगसी सिरिजंगा उच्चतर माध्यमिक स्कूल का दौरा किया। उनके साथ कृषि विभाग के सलाहकार दुर्गा प्रसाद प्रधान और विभागीय अधिकारी भी थे।

मंत्री शर्मा ने स्कूल परिसर में अतिरिक्त निर्माणाधीन स्कूल भवन का निरीक्षण किया।

उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य प्रदीप गुरुंग और स्कूल स्टाफ के साथ भी बातचीत की और स्कूल की गतिविधियों और सुविधाओं और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली।

नई सरकार गठन के बाद राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कामों के बारे में भी जानकारी दी।

सिक्किम में ऑर्किड विषय पर एक दिवसीय विचार मंथन कार्यशाला आयोजित

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 11 फरवरी । यहां के पांगथांग स्थित जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन इनवायरोमेंट की ओर से एक दिवसीय विचार मंथन कार्यशाला आयोजित किया। सिक्किम में आर्किड विषय पर जागरुकता और इसके संरक्षण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आईसीएआर आर्किड अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक, डा. कलाईवनम एनएस, एसएस विश्व आदि उपस्थित थे।

विचार-मंथन कार्यशाला का एकमात्र उद्देश्य संस्थानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान का आदान-प्रदान करना और एक ऐसा नेटवर्क बनाना था जो समग्र अनुसंधान दृष्टिकोण ला सके। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रमुख, जीबीपी-एनआईएचई, सिक्किम क्षेत्रीय केंद्र डॉ राजेश जोशी ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि संस्थान ने आर्किड ट्रेल और आर्किडेरियम विकसित करके सिक्किम में आर्किड के संरक्षण और कार्यात्मक लक्षणों पर लाइव प्रदर्शन की दिशा में काम करने की शुरुआत की है। इससे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समर्थित नेचर लर्निंग सेंटर परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों, कॉलेज के छात्रों, शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए प्रकृति संरक्षण के लाइव मॉडल प्रदर्शित करना है। विचार-मंथन सत्र के दौरान परिसर में आर्किड ट्रेल के सुदृढ़ीकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

आर्किडेरियम की स्थापना और विकास के लिए क्रियान्वित करने के संबंध में विभिन्न योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें विभिन्न थीम आधारित आर्किड का चयन करना शामिल था।

सत्र के बाद, आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड की टीम ने संस्थान के नेचर लर्निंग सेंटर का दौरा किया, जहां विशेषज्ञ ने संस्थान में आर्किड संरक्षण को और मजबूत करने के लिए ऑर्किड से संबंधित विभिन्न तकनीकी ज्ञान साझा किए। दोनों संस्थान सिक्किम में ऑर्किड के प्रति जागरुकता और संरक्षण के लिए ज्ञान नेटवर्किंग के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान और संयुक्त प्रयासों के लिए सहमत हुए। इसके लिए रोडमैप भी तैयार किया गया है।

कार्यशाला का आयोजन हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा समर्थित हिम-नेचर लर्निंग सेंटर परियोजना के एक भाग के रूप में किया गया था।

कार्यशाला के दौरान जीबीपीएनआईएचई के वैज्ञानिक डॉ. देवेंद्र कुमार, डॉ. संदीप रावत, डॉ. मयंक जोशी, तकनीकी कर्मचारी जे ढकाल, पीके तमांग, एनएलसी परियोजना की टीम प्रकाश छेत्री आदि उपस्थित थे।

शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर मिले तीन पुरस्कार

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 11 फरवरी । शिक्षा विभाग सिक्किम सरकार को तीन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उक्त राष्ट्रीय पुरस्कार शैक्षिक प्रशासन और योजना में नवाचार और बेहतर अभ्यास के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) द्वारा प्रदान किया गया है। एनआईईपीए शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में एक स्वायत्त निकाय है। यह शैक्षिक रोजगार और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता आया है।

एनआईईपीएल ने साल 2014 में शैक्षिक प्रशासन में नवाचार और बेहतर अभ्यास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना आरंभ की थी। यह पुरस्कार जिला शिक्षा अधिकारी और खंड स्तरीय अधिकारियों के लिए क्षेत्र स्तरीय शैक्षिक प्रशासन में दिए हुए योगदान को मान्यता देते हुए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार विजेताओं का चयन उच्च स्तरीय अधिकारी, प्रशासन और शिक्षाविद समूह करते हैं।

वर्ष 2028-19 और 2019-20 के लिए शैक्षिक प्रशासन में नवाचार और बेहतर अभ्यास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गुरुवार को वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार मुख्य अतिथि थे। केंद्रीय मंत्री ने पुरस्कार के लिए चयनित अधिकारियों को आभासी माध्यम से पुरस्कार प्रदान किया।

वर्ष 2018-19 के लिए 36 अधिकारियों ने राष्ट्रीय पुरस्कार और सात अधिकारियों ने प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इसके साथ ही साल 2019-20 के लिए 55 अधिकारियों ने राष्ट्रीय पुरस्कार और 12 अधिकारी ने प्रशंसा पत्र प्राप्त किया है। साल 2019-20 के 55 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं में सिक्किम के तीन अधिकारी भी शामिल है।

विजेताओं में अम्बर दास छेत्री (संयुक्त निदेशक, समग्र शिक्षा), पद्मलाल सुब्बा (संयुक्त निदेशक, गेजिंग) और सुन्दर कुमार राई (सहायक शिक्षा अधिकारी, डुगा बीएसी) हैं।

सिक्किम के भविष्य को जोखिम में डाल रही है सरकार : रूपेन कार्की

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 11 फरवरी । सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम (एसपीवाईएफ) ने बड़ी संख्या में संचालित कोइरी और अवैध पेड़ कटान की आलोचना करते हुए आपत्ति जताई है। एसपीवाईएफ का आरोप है कि अवैध बालू खनन और पत्थरों की निकासी पूर्व सरकार में भी हुई थी लेकिन वर्तमान सरकार में यह और अधिक बढ़ गया है।

एसपीवाईएफ सदस्य रूपेन कार्की ने सिक्किम के विभिन्न स्थान में कोइरी और अवैध रूप में बालू और पत्थर निकालने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व पश्चिम जिले के कालेज खोला में भी बालू और पत्थर निकालने का काम हो रहा था, लेकिन एसपीवाईएफ के हस्तक्षेप के बाद वहां काम बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि आम लोग नदी में जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन नदी बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कार्यों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

उन्होंने कहा कि पूर्व जिले के रोड़ाथांग की स्थिति भी सोचनीय बन गई है। संबंधित विभाग ने कुछ व्यक्तियों को छूट दी है। ऐसे कामों को तत्काल बंद करना चाहिए। इसके अलावा कार्की ने अफेक्टेड सिटिजन्स आफ तिस्ता (एक्ट) की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार जिसने पहले तो विरोध किया था लेकिन फिर सत्ता में आने के उसने भी इस नए जल विद्युत परियोजना को शुरू कर दिया है। रूपेन कार्की ने कहा कि कुछ लोगों के फायदे के लिए सिक्किम के भविष्य को जोखिम में डालने का काम बंद होना चाहिए।

फोरम के सदस्य शंकर शर्मा ने निर्धारित न्यूनतम वेतन में संशोधन करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसकी तुलना में वेतन उपयुक्त नहीं है।

उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप समान वेतन समान काम नीति लागू करने की अपील की। दूसरी ओर फोरम के सदस्य लेखक शर्मा ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में बस सेवा शुरू करने की मांग की है।

उन्होंने वाहनों के विभिन्न टैक्स में हुई बढ़ोत्तरी का विरोध करते हुए कहा कि इसकी मार आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। उन्होंने बढ़ाए गए टैक्स को कम करने की मांग करते हुए वाहन किराए को भी नियंत्रित करने की मांग की।

राज्यपाल ने जरूरतमंदों को बांटा कंबल

अनुगामिनी नि.सं.

रंगपो, 11 फरवरी । आज रंगपो विंटर कैम्प में रंगपो नगर पंचायत की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल गंगा प्रसाद ने वरिष्ठ एवं जरूरतमंद नागरिकों में कम्बल वितरण किया। कार्यक्रम में रंगपो नगरपालिका अध्यक्ष संजीव कुमार खाती, एसडीएम रंगपो मिलन राई, एसडीपीओ रंगपो दिलीप तमांग रंगपो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रधानध्यापक डॉक्टर ह्ना योंजन, बीडीओ डूगा आईबी छेत्री, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, श्रद्धा स्वयंसहायता समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सिक्किम में उत्पादित जैविक वस्तुएं जैसे शुद्ध शहद, फल, सब्जियों की खेती पर ध्यान दिया जाए तो राज्य के आय में वृद्धि होगी। आगे उन्होंने नगर पंचायत के सदस्यों से मिलकर कार्य करने का आग्रह करके एक मजबूत राष्ट्र निर्माण की नींव रखने में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। ग्राम पंचायत के वरिष्ठ नागरिकों एवं स.फ़ाई कर्मचारियों के लिए राजभवन के परिसर में भोजन की भी व्यवस्था की गई थी।

हमारी सुरक्षा महासागरों से जुड़ी : पीएम मोदी

राजेश अलख

नई दिल्ली, 11 फरवरी । भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के न्योते पर 'वन ओशियन समिट' को संबोधित किया। यहां पीएम ने कहा, 'मैं महासागर के लिए इस महत्वपूर्ण वैश्विक पहल के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को बधाई देता हूं। भारत की सभ्यता हमेशा से समुद्र से जुड़ी सभ्यता रही है। आज हमारी सुरक्षा और समृद्धि भी महासागरों से जुड़ी हुई है। भारत की पहल 'इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव' का भी प्रमुख स्तंभ समुद्री संसाधन हैं।

पीएम ने महासागर और समुद्रों के प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा, 'भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्र से प्लास्टिक और कचरे को साफ करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया गया जिसमें युवाओं ने 13 टन प्लास्टिक कचरा एकत्र किया।'

सीएम कार्यालय ने सीएम के पिता कालू सिंह तमांग के निधन पर जताया शोक

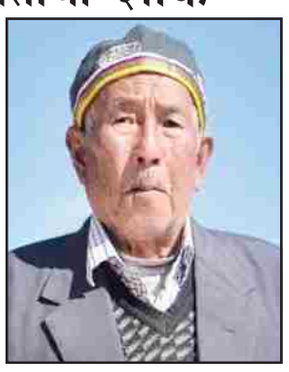

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 11 फरवरी । सिक्किम सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के पिता कालू सिंह तमांग के निधन पर आज श्रद्धांजलि संदेश जारी किया गया।

मुख्यमंत्री के सचिव एसडी ढकाल की ओर से जारी एक संदेश में कहा गया है कि स्वर्गीय कालू सिंह तमांग का जन्म पश्चिम जिले के सिंगलिंग में 02 मई 1928 में हुआ था। उनके पिता का नाम दावा तमांग और माता का नाम मार्दोल्मो तमांग था। स्वर्गीय कालू सिंह तमांग ने सेंग स्ल में जूनियर सेकेंडरी स्तर तक पढ़ाई की और सोरेंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आदेशपाल के पद पर काम किया।

इसमें उल्लेख किया है कि उन्होंने इस संप्रदाय में पढ़ाने वाले अन्य शिक्षकों की मदद करते प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में अपना योगदान दिया है। उन्हें प्यार से सभी लोग मामा बुलाते थे। वह अपने परिवार के समर्थन के लिए कृषि और डेयरी खेती में लगे हुए थे।

सचिव ढकाल ने उल्लेख किया है कि कालू सिंह तमांग ने अपनी नौकरी से अवकाश लेने के बाद दो बार पंचायत चुनाव लड़ा था। वह पंचायत उपाध्यक्ष भी रहे थे। वह पश्चिम सिक्किम स्थित सिंगलिंग गुंपा समिति के कार्यकारी सदस्य भी थे। स्वर्गीय कालू सिंह तमांग का 09 फरवरी 2022 को निधन हुआ। वे अपने पीछे धर्मपत्नी श्रीमती धनमाया तमांग, चार बेटे, चार बेटियां और 14 पोते-पोतियां और तीन परपोते छोड़कर गए हैं।

चुनाव के बाद आंदोलन के लिए तैयार रहें किसान : राकेश टिकैत

इगलास (अलीगढ़), 11 फरवरी (एजेन्सी)। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को धारा की गढ़ी में किसानों के साथ संवाद कर कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद आंदोलन करने के लिए तैयार रहें। कहा कि एमएसपी पर फसलों को खरीदे जाने के लिए कमेटी गठन व कृषि कानूनों समेत किसानों की समस्याओं पर संसद सत्र में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है।

उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, जनप्रतिनिधियों पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर भाकियू चुप नहीं बैठेगी। संसद का सत्र चला लेकिन किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार (शेष पृष्ठ ०३ पर)

बसपा का हाथी और सपा के गुंडे खा गए गरीबों का राशन : योगी

बदायूं, 11 फरवरी (एजेन्सी)। वजीरगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना कॉल हो या फिर उससे पहले और उसके बाद गरीबों को जो राशन मिल रहा है, बहरापन भाजपा सरकार ही नहीं उससे पहले की सरकारें भी दे सकती थी। मगर पहले की बसपा सरकार के हाथी का इतना बड़ा पेड़ था जिसकी वजह से गरीबों को राशन भत्ता ही नहीं था, दूसरी सपा की सरकार मैं भी गरीबों का राशन गुंडा और माफिया खा गए। बोले कोरोना कॉल में आपकी मदद करने भाजपा के लोग भी आए थे बाकी दिल्ली के दो भाई बहन और बहन जी दिखाई नहीं दी थीं। अखिलेश यादव तो आतंकवादियों को छुड़ाने का काम करते हैं।

शुक्रवार को बदायूं जिले के वजीरगंज कटरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा आयोजित की गई। यहां बदायूं विधानसभा से महेश चंद्र गुप्ता और बिल्सी विधानसभा से हरीश शाक्य, बिसौली विधानसभा से कुशाग्र सागर और सहसवान विधानसभा से डीके भारद्वाज के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 के इस चुनाव में भाजपा विकास के दम पर लौट रही है। बोले केंद्र में मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है।

भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार के विकास करने की रफ्तार भी डबल है इसीलिए इन 5 वर्षों में विकास का परिणाम भी आपके सामने डबल है।

बोले बदायूं से मां गंगा की कृपा से गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है जो यूपी में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है इसका लाभ भी सबसे ज्यादा बदायूं के लोगों को मिलेगा। बोले सपा की सरकार जब 2012 में बनी थी तो अखिलेश यादव का सबसे पहला काम आतंकवादियों को छुड़वाने था, बोले 2017 के चुनाव में जब भाजपा की सरकार बनी तब भाजपा की सरकार का सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी रहा।

बोले भाजपा सरकार में यूपी से पेशेवर माफियाओं का सफाया हो चुका है गुंडा किनारा कर चुके हैं। बोलो बदायूं विधानसभा से जो

प्रत्याशी हैं महेश चंद्र गुप्ता वह मेरी सरकार में मंत्री भी रहे हैं और उनकी मूंछ बहुत लंबी है। बोले अब उनको जब आप अपना वोट देकर दोबारा से विधायक बनाएंगे तो हम उनकी मूंछ और ज्यादा टाइट कर देंगे।

बोले इसके बाद बदायूं के भी गुंडे माफिया गले में तख्ती लटका कर किनारा करते नजर आएंगे। कहा कि सपा के अखिलेश कहते हैं हमने भी विकास कराया है जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवाई हैं, बोले भाइयों बहनों इस चुनाव में वोट तमाशा मार कर अखिलेश यादव को बता देना जिन की बाउंड्री वॉल बनवाई है वोट भी वही देंगे।

भारत के 257 थानों में वाहन नहीं, 638 के पास में पफोन की सुविधा नहीं, संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली, 11 फरवरी (एजेन्सी)। संसद की एक स्थायी समिति ने गुरुवार को संसद में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि देश में 257 थानों में वाहन नहीं हैं और 638 में टेलीफोन नहीं हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति ने कहा कि एक जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार देश में 16,833 थानों में से 257 थानों में वाहन नहीं है, 638 थानों में टेलीफोन नहीं है और 143 थानों में वायरलैस या मोबाइल फोन नहीं हैं।

समिति ने कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे बहुत संवेदनशील सीमावर्ती केंद्रशासित प्रदेश में भी ऐसे थाने बड़ी संख्या में हैं, जिनमें टेलीफोन और वायरलैस सेट नहीं हैं। समिति ने सिफारिश की है कि गृह मंत्रालय ऐसे राज्यों को सलाह दे सकता है कि उनके थानों में पर्याप्त वाहन और संचार उपकरणों की व्यवस्था की जाए।

समिति ने बताया कि राज्य पुलिस बलों में 5.30 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों के पद खाली पड़े हैं और इस तरह कुल स्वीकृत संख्या की तुलना में बल में 21 प्रतिशत की कमी है। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य पुलिस बलों में 26,23,225 पदों की स्वीकृत संख्या की तुलना में एक जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार पुलिस बल में 5,31,737 पद खाली हैं और इस तरह पुलिस बल में करीब 21 प्रतिशत पद खाली हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के अनुसार खाली पड़े पदों में अधिकतर कांस्टेबल स्तर के हैं।

सरकार ने राज्यसभा में कहा कि किसानों के आंदोलन के केंद्र में रहे और बाद में वापस ले लिये गए तीन कृषि कानूनों को फिर से लाने की उसकी कोई योजना नहीं है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उच्च सदन में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि वापस लिए गए तीन कृषि कानूनों को भविष्य में फिर से लाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 14 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट चर्चा पर जवाब देने के बाद शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही बजट सत्र का पहला चरण भी समाप्त हो गया है। सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से आठ अप्रैल तक चलेगा।

इस बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, द्रमुक और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक टिप्पणी का विरोध करते हुए शुक्रवार को लोकसभा से वाकआउट किया। दरअसल, योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को आगाह करते हुए दावा किया है कि अगर इस बार मतदाता चूक गए तो उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही कई विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए। कुछ सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए।

विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि अफगानिस्तान के हालात भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए स्वाभाविक चिंता का विषय है और मध्य एशियाई देश भी ऐसी ही चिंता और उद्देश्य प्रकट करते हैं। भारत ने जनवरी में पहले भारत-मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान ने वर्चुअल माध्यम से शिरकत की थी।

तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय के सवाल पर मुरलीधरन ने कहा कि सम्मेलन में अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। भारत और पांच मध्य एशियाई देशों ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर संयुक्त कार्यबल के गठन का फैसला लिया। सम्मेलन के बाद जारी दिल्ली घोषणा में अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय सहायता, आतंकवाद व ड्रग तस्करी से निपटने, महिलाओं, बच्चों व अल्पसंख्यकों के अधिकारियों के संरक्षण की बात कही गई थी। साथ ही भारत और मध्य एशियाई देशों के नेताओं ने हर दो साल पर सम्मेलन करने का भी निर्णय लिया। अगला सम्मेलन 2024 में होने की उम्मीद है।

लोकसभा में शुक्रस्वार को प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों की अनुपस्थिति पर विपक्ष ने हंगामा किया। विवाद उस समय शुरू हुआ जब रक्षा मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न का जवाब कानून मंत्री किरेन रिजिजू देने लगे। उस दौरान सदन में न तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और न ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। विपक्ष ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के कारण मंत्री सदन का अपमान कर रहे हैं।

मुकुल राय को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका खारिज

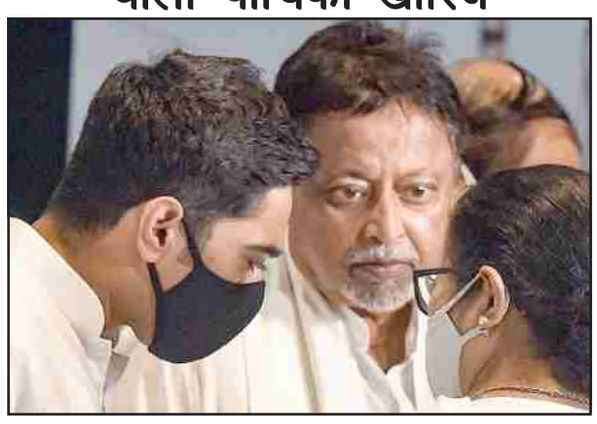

कोलकाता, 11 फरवरी (एजेन्सी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने मुकुल राय को विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि दलबदल विरोधी कानून के तहत चुनाव के बाद पार्टी बदलने के लिए मुकुल राय को एक विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय पिछले साल जून में पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए थे। विधानसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में सुनवाई पिछले महीने पूरी हो गई थी। विधानसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि कानून के अनुसार रॉय सदन में भाजपा विधायक के रूप में बने रहेंगे।

इस फैसले को लेकर बिमान बनर्जी ने कहा कि याचिकाकर्ता आपेक्षित साक्ष्य पेश नहीं कर सके। मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और कानून के तहत मैंने पाया कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका में बताए गए तर्कों को साबित करने में सक्षम नहीं है। इस वजह से मैंने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि निष्कर्ष निकालना आपके ऊपर है, मैंने सबूतों के अभाव में याचिका खारिज की है।

भाजपा विधायक अंबिका रॉय ने भी मुकुल रॉय को सार्वनिक लेखा समिति (पीएसी) का चेयरमैन नियुक्त किए जाने के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने मांग की है कि इस पद पर परंपरा के अनुसार विपक्ष के सदस्य को नियुक्त किया जाए। हाईकोर्ट ने बिमान बनर्जी से कहा था कि रॉय को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर फैसला लें।

स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक एजेंडे के साथ हुई क्वाड बैठक, भारत में आतंकी हमलों की निंदा

मेलबर्न, 11 फरवरी (एजेन्सी)। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने चौथी क्वाड (चार देशों का समूह) विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए शुक्रवार को मेलबर्न में मुलाकात हुई, जहां उन्होंने एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के प्रयासों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

इंडो-पैसिफिक एक ऐसा क्षेत्र है, जो समावेशी और लचीला है और इसमें यह राष्ट्र जबरदस्ती वाली प्रक्रिया से मुक्त होकर अपने लोगों के हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं।

क्वाड विदेश मंत्रियों ने मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया (एचएडीआर), समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, दुष्प्रचार का मुकाबला करने और साइबर सुरक्षा सहित क्षेत्रीय चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। यह भी निर्णय लिया गया कि जापान 2022 की पहली छमाही में अगले क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है।

क्वाड समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून, शांति और सुरक्षा, भारत-प्रशांत के विकास और समृद्धि को रेखांकित करता है और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के महत्व पर जोर देता है।

ये चारो देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के क्वाड गठबंधन का हिस्सा हैं, जिसे चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के मकसद से बनाया गया था।

क्वाड हमेशा विकसित होने वाले खतरों और हिंद-प्रशांत देशों के साथ काम करने और बहुपक्षीय मंचों पर सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहा है और सीमा पार आतंकवाद के लिए आतंकवादी प्रॉक्सी के उपयोग की निंदा करता है और देशों से मिलकर काम करने का आग्रह करता है। इसका उद्देश्य आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म करना, आतंकवादी नेटवर्क और उन्हें बनाए रखने वाले बुनियादी ढांचे और वित्तीय चैनलों को बाधित करना और आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को रोकना है।

क्वाड की ओर से संयुक्त बयान में कहा गया है कि 26/11 मुंबई और पठानकोट हमलों सहित भारत में आतंकवादी हमलों की निंदा दोहराई गई है और इसने यूएनएससी प्रस्ताव 2593 (2021) की पुष्टि की है कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या हमला करने, आश्रय या आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसने कहा है कि आतंकवादी कृत्यों की योजना या वित्त पोषण, इस तरह के अनियंत्रित स्थान हिंद-प्रशांत की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा हैं।

इसने कहा है कि आसियान एकता एवं केंद्रीयता और आसियान के नेतृत्व वाली वास्तुकला के अटूट समर्थकों के रूप में, क्वाड भारत-प्रशांत पर आसियान के ऑष्टिकोण के व्यावहारिक कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए आसियान भागीदारों का समर्थन करना जारी रखे हुए है। क्वाड मेकांग उप-क्षेत्र सहित उप-क्षेत्रीय तंत्र और संस्थानों के महत्व को स्वीकार करता है और वे 2022 आसियान अध्यक्ष के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में कंबोडिया का समर्थन करना जारी रखेंगे।

बैठक में, यह नोट किया गया कि क्वाड भागीदारों ने सामूहिक रूप से 50 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक प्रदान की हैं और वैश्विक स्तर पर 1.3 अरब से अधिक वैक्सीन खुराक दान करने का वचन दिया है। इसने भारत में बायोलॉजिकल ई-लिमिटेड सुविधा में वैक्सीन उत्पादन के विस्तार में क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की तीव्र प्रगति को भी नोट किया, जिसका उद्देश्य 2022 के अंत तक कम से कम 1 अरब टीके वितरित करना है।

क्वाड स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित करने, टीके की झिझक से निपटने और बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से कोल्ड चेन सिस्टम को लास्ट माइल वैक्सीन डिलीवरी के लिए प्रशिक्षित करने में भी सहायता कर रहा है।

बयान में कहा गया है, हम वैश्विक कार्य योजना के तहत कोविड महामारी से निपटने के लिए प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए समय पर पहल का स्वागत करते हैं।

भाजपा का आरोप, देवभूमि के स्कूलों में हिजाब लाने की कोशिश कर रही कांग्रेस

नई दिल्ली, 11 फरवरी (एजेन्सी)। उत्तराखंड में मतदान से कुछ दिन पहले भाजपा ने दावा किया है कि कांग्रेस 'देवभूमि' के स्कूलों में हिजाब लाने की कोशिश कर रही है।

सत्तारूढ़ भाजपा पहले ही दावा कर चुकी है कि 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए कांग्रेस ने जानबूझकर 'मुस्लिम विश्वविद्यालय' विवाद खड़ा किया है।

बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस 'देवभूमि' में हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) और उत्तराखंड में पार्टी युवा विंग के प्रभारी तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आईएएनएस से कहा कि अगर देवभूमि में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो स्कूलों में हिजाब पहना जाएगा।

उन्होंने कहा, 'अगर कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता में आती है, तो वे वही करेंगे जो वे कर्नाटक में करने की कोशिश कर रहे हैं। देवभूमि के स्कूलों में हिजाब पहना जाएगा। हम देवभूमि में इस तरह के कृत्य की अनुमति नहीं देंगे और कांग्रेस पार्टी को इस देवभूमि से दूर रखा जाना चाहिए।'

बग्गा ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और हरीश रावत जो कुछ भी करेंगे, देवभूमि उत्तराखंड के स्कूलों में हिजाब की अनुमति नहीं होगी।

बग्गा ने आगे दावा किया कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में मिली हार को देखकर कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी और हरीश रावत तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'उत्तराखंड में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस और उसका नेतृत्व उन्हें खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा है।'

इससे पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण के लिए मुस्लिम विश्वविद्यालय पर विवाद खड़ा किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष अकील अहमद ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आश्वासन दिया था कि उत्तराखंड में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अहमद के दावों का खंडन किया है। भाजपा ने कहा है कि विपक्षी दल राज्य में समुदाय के लिए मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा करके कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 'मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण' करने की कोशिश कर रहा है।

उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के साथ 'वोट बैंक' जैसा व्यवहार कर रही है और विश्वविद्यालय का वादा कर अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रही है।

अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम से करेंगे एक प्रमुख चौराहा : योगी

कासगंज, 11 फरवरी (एजेन्सी)। पहले चरण के चुनाव के बाद सीएम योगी ने शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के कई शहरों में जनसभाएं कीं। बदायूं के बाद कासगंज पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का भी नाम भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर होना चाहिए।

ये हमारा संकल्प है। इसके बाद उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। कासगंज में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, हम यहां मुंबई की फिल्म सिटी ला रहे हैं। युवाओं को फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। हमने भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में एक अकादमी बनाने का भी फैसला किया है। हमने बिना किसी भेदभाव के सभी को कल्याणकारी योजनाएं प्रदान की हैं।

बदायूं पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को तंज कसते हुए कहा कि कब्रिस्तानों का विकास करने वाली समाजवादी पार्टी के लिए वोट भी उसी जगह से आएंगे।

बदायूं की सदर विधानसभा सीट के प्रत्याशी महेश गुप्ता के प्रचार के लिए कस्बा वजीरगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि सपा ने विकास के नाम पर सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल बनवाई। जब विकास कब्रिस्तान का करवाया है तो वोट भी वहीं से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यहां माफिया व्यापारियों का उत्पीड़न करते थे, भू-माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया करते थे, शोहदे और शरारती तत्व लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे।

वह स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी,मगर आज भू-माफिया गायब हो चुके हैं, जो माफिया और शोहदे लड़कियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने थे, वे अपने गले में पट्टा डाल कर स्वयं जान की भीख मांगते हुए थाने थाने घूम रहे हैं। योगी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे बनने का बड़ा लाभ बदायूं के लोगों को मिलेगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच बसे इस जिले में जब इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगा, तो सबसे ज्यादा नौकरियां क्षेत्र को मिलेंगी।

2 मार्च से दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में शुरू होगी फिजिकल सुनवाई

राजेश अलख

नई दिल्ली, 11 फरवरी । दिल्ली हाईकोर्ट और राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों में 2 मार्च से पूरी तरह से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू होगी।

शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। आदेश के अनुसार, हालांकि, मामला-दर-मामला (केस-टू-केस) आधार पर असाधारण परिस्थितियों में, अदालत एक हाइब्रिड वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की अनुमति दे सकती है।

मुख्य न्यायाधीश के निदेर्शानुसार, 14 फरवरी से फिजिकल सुनवाई के लिए अदालत की उचित संख्या में पीठों का गठन किया जाएगा।

शेष बेंच वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों पर सुनवाई जारी रखेंगी। हालांकि, सभी बेंच मामलों को सूचीबद्ध करने की मौजूदा प्रणाली के अनुसार मामलों की सुनवाई करेंगी।

इसमें कहा गया है कि उनमें से लगभग 50 प्रतिशत फिजिकल (शारीरिक रूप से) मामले अदालत में आते हैं जबकि अन्य मामलों को वर्चुअल यानी आभासी मोड के माध्यम से उठाते हैं।

अधिवक्ता, अन्य कर्मचारी और अधिकारियों, वादी और अदालतों में आने वाले अन्य आगंतुक केंद्र, दिल्ली सरकार और अदालत प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा दिशानिदेशरें आदि का पालन करेंगे। सभी हितधारकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द खुद को टीका लगवाएं।

महामारी की तीसरी लहर के बीच दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला अदालतें 3 जनवरी से केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई कर रही हैं।

गिरिराज सिंह ने समान नागरिक संहिता को बताया समय की मांग, विपक्ष पर भी साधा निशाना

नई दिल्ली, 11 फरवरी (एजेन्सी)। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर देश में बवाल जारी है। कर्नाटक से निकलकर ये विवाद देश के कई शहरों में पहुंच गया है। मालेगांव में भी महिलाओं ने शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहन कर जाने देने की मांग की। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता समय की मांग बन गई है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि प्रांत और धर्म के नाम पर देश को कोने-कोने से तोड़ने का प्रयास प्रतिदिन किया जा रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता समय की मांग बन गई है। अब कुछ खास वर्ग के लोग ने देश का कानून तय करना शुरू कर दिया है।

इस कड़ी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार बोले कि कुछ चरमपंथी छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा जींस पहनने वाली मुस्लिम लड़की मुस्कान खान के जरिए कुछ चरमपंथियों हमारे देश और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह साबित करता है कि चरमपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर ले जा रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

कर्नाटक में एक जनवरी से हिजाब पर विवाद शुरू है। जब एक शिक्षण संस्थान में 6 मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास करने से मना कर दिया गया। कॉलेज प्रबंधन ने हिजाब को कॉलेज के ड्रेस नियमों के खिलाफ बताया।

तब से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुस्लिम लड़कियां कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने देने की अनुमति देने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि वे उनके धर्म के अनुसार इसे पहनकर क्लास में बैठना चाहती हैं। इसी मामले को लेकर महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। वहीं पुलिस ने शुक्रवार को बिना अनुमति मालेगांव में प्रदर्शन करने पर चार आयोजकों पर धारा 144 के उल्लंघन में केस दर्ज किया है।

अखिलेश के राज में कभी गरीबों का भला नहीं हुआ : अमित शाह

बरेली, 11 फरवरी (एजेन्सी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश के राज में कभी भी यूपी के गरीबों का भला नहीं हुआ।

अमित शाह आज यहां एक चुनावी जनसभा में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं पर निशाना साधा। अमित शाह बोले ''अखिलेश के राज में कभी यूपी के गरीबों का भला नहीं हुआ।''

गृह मंत्री ने कहा कि पहले चरण में सपा-आरएलडी साफ हो चुकी है। उन्होंने कहा, ''मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि भाजपा तीन सौ सीटो से पार जा रही है। एक बार फिर योगी सरकार बन रही है। 2017 से पहले जब मैं यूपी आता था तो एक ही मांग थी कि गुंडाराज खत्म कर दो। आज योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रूहेलखंड से गुंडाराज खत्म कर दिया है।''

गृह मंत्री ने आगे कहा, ''उत्तर प्रदेश के तीन बड़े माफिया नाम है- आजम खां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। अब ये तीनों जेल में है। गलती से भी सपा की सरकार बनी तो ये तीनों जेल में रहेंगे क्या। ये भाजपा ही है जो माफियाओं को जेल भेजती है।''

अमित शाह ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी अर्थव्यवस्था में छठें नंबर पर था, आज योगी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर पर लाया है। हम धारा 370 हटाना चाहते थे और अखिलेश बाबू विरोध करते थे, कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा मोदी के सबका साथ-सबका वि कास के नारे पर चलती है।योगी सरकार ने यूपी से माफिया राज को खत्म किया। आज अतीक अहमद, आजम खान जेल में हैं। लोगों में भय का माहौल खत्म हुआ है।

उन्होंने कहा कि भाजपा मोदी के सबका साथ-सबका विकास के नारे पर चलती है। योगी सरकार ने यूपी से माफियाराज को खत्म किया। लोगों में भय का माहौल खत्म हुआ है। भाजपा की सरकार ने दो करोड़ घरों में शौचालय बनवाया। आज गरीबों को इलाज के लिए भाजपा ने हर गरीब को 5 लाख तक का सारा इलाज आयुष्मान कार्ड से मुफ्त कराया।

उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तो समाजवादी पार्टी रखा है, लेकिन अखिलेश बाबू ने गरीबों को इलाज नही मुहैया कराया था।

परिवार वाला व्यक्ति झोला लेकर नहीं भागेगा : अखिलेश

लखनऊ, 11 फरवरी (एजेन्सी)। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाई-भतीजावाद और वंशवाद की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उन पर किए गए हमले के लिए पलटवार किया है।

उन्होंने एक बयान में कहा कि जिनके परिवार नहीं हैं वे इस पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों ने क्या झेला है। मैं कहना चाहता हूं कि जिनके पास परिवार हैं वे ही एक परिवार के दर्द को समझ सकते हैं। मुझे गर्व है कि मेरे पास परिवार है।

अखिलेश ने आगे कहा कि परिवार का कोई व्यक्ति झोला लेकर नहीं भागेगा और परिवार को पीछे नहीं छोड़ देगा। लॉकडाउन के दौरान अगर मुख्यमंत्री का परिवार होता तो वह अपने घर पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलने वाले मजदूरों का दर्द समझते।

उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने आखिरी घोषणापत्र के लिए दो मिनट का मौन रखना चाहिए क्योंकि वे पांच साल पहले किए गए वादों को पूरा नहीं कर सके।

सपा प्रमुख ने पहले चरण के मतदान के दौरान कई बूथों पर ईवीएम के ठीक से काम नहीं करने की खबरों पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि कई रिपोर्टें थीं कि ईवीएम ठीक से काम नहीं कर

रही थी, मतदान घंटों तक रोक दिया गया था और लोगों को वोट डालने के लिए इंतजार करना पड़ा था। निष्पक्ष चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग द्वारा सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के बारे में अखिलेश ने कहा कि सरकार को सख्त सजा सुनिश्चित करनी चाहिए थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से विफल रही। दुनिया ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना को देखा है। हर कोई इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि भाजपा आरोपियों को बचा रही है।

सीबीआई की कार्रवाई : रिश्वतखोरी के मामले में रेलवे अधिकारी गिरफ्तार, बरामद की 1.22 करोड़ की नकदी

नई दिल्ली, 11 फरवरी (एजेन्सी)। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक रवि शेखर सिन्हा को गिरफ्तार किया है। सिन्हा के खिलाफ यह कार्रवाई 1.80 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में की गई है। एजेंसी ने उसके विभिन्न परिसरों पर तलाशी के दौरान 1.22 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की है।

जांच एजेंसी के प्रवक्ता आरसी जोशी ने शुक्रवार को बताया कि मामले में पांच और लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। जाल बिछाकर की गई गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने 1986 बैच के भारतीय रेलवे स्टोर्स सर्विस के अधिकारी सिन्हा के दिल्ली, पंचकुला, चंडीगढ़, वाराणसी और बंगाल के चितरंजन में 17 परिसरों पर तलाशी थी।

जोशी ने बताया कि छापेमारी के दौरान लगभग 1.22 करोड़ रुपये की नकदी, करीब 500 ग्राम सोना और ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, पटना और रांची में स्थित संपत्तियों से जुड़े हैं। वहीं, अन्य आरोपियों के परिसरों से करीब 32 लाख रुपये नकद और दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

एजेंसी को जानकारी मिली थी कि ईसी ब्लेड्स एंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों सोनी अरोड़ा और राजन गुप्ता रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर साजिश रच रहे थे और अवैध तरीकों से बिल पारित करवा रहे थे। इसके बाद सिन्हा, अरोड़ा, गुप्ता और अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया।

मामले में अन्य सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी कंपनी के दोनों निदेशकों को चंडीगढ़ के सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया गया था।

जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सिन्हा को चितरंजन में 1.80 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।

चुनाव के बाद .....

ने कोई चर्चा नहीं की। किसानों से बात करने के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई थी लेकिन कमेटी नहीं बनी। इससे सरकार की मंशा में खोट लग रहा है। किसान विरोधी काले कानून व किसान विरोधी नीतियों को लेकर विधानसभा चुनाव के बाद लड़ाई लड़नी पड़ेगी।

उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि विधानसभा चुनाव के बाद आंदोलन करने के लिए कमर कस लें। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कुछ छात्र नेता भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता से मिले तथा भाकियू में अपनी आस्था जताई। इस मौके पर टीकम सिंह सूर्यवंशी को भाकियू का जिला प्रवक्ता बनाया गया। भाकियू के राष्ट्रीय महामंत्री राजपाल शर्मा, जिलाध्यक्ष कमांडो ओपी सिंह, युवा विंग के अध्यक्ष रामकिशोर गौतम, मुकेश कुमार, अमित कुमार, बच्चू सिंह, जगराम सिंह, विजयपाल सिंह, ऐदल सिंह, भूरा उपाध्याय मौजूद रहे।

भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गोरई गांव पहुंचकर डॉ. हरचरन सिंह के परिवार से मुलाकात की। पिछले दिनों हुए डॉ. हरचरन के असामयिक निधन पर शोक संवेदना प्रकट कीं। शोक संतप्त परिवार वालों को ढाढ़स बंधाया।

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 08:00 PM

DEAR VULTURE EVENING

Draw No:163 DrawDate on:11/02/22

1st Prize ₹1 Crore/- 57E 00595

Cons. Prize Rs.1000/- 00595 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-
04909 14181 26765 29247 33998 55730 69224 77892 83522 90018

3rd Prize ₹450/-
0609 0929 3637 3789 4174 5227 6684 7149 8194 9748

4th Prize ₹250/-
0198 5417 5582 5816 6354 7741 7935 8279 9763 9843

5th Prize ₹120/-
0067 0182 0214 0318 0333 0360 0445 0833 0861 0962
1009 1077 1288 1401 1478 1530 1553 1644 1713 1786
1923 1938 1990 1992 2113 2115 2307 2397 2502 2576
2582 2697 2698 2809 3368 3473 3512 3569 3770 3820
3949 4021 4082 4139 4294 4367 4368 4386 4445 4824
4934 5040 5134 5136 5282 5584 5698 5700 5755 5925
5933 5990 6010 6028 6055 6216 6253 6389 6478 6479
6518 6537 6734 6868 7096 7180 7198 7351 7354 7378
7597 7661 7678 7801 7861 8092 8247 8412 8497 8840
8897 8998 9063 9085 9140 9355 9766 9777 9819 9999

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 01:00 PM

DEAR HOOGHLY MORNING

Draw No:63 DrawDate on:11/02/22

1st Prize ₹1 Crore/- 58L 09896

Cons. Prize Rs.1000/- 09896 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-
08154 26359 49908 54423 68759 79885 87430 90586 91392 94634

3rd Prize ₹450/-
3064 3843 4997 5168 5412 5779 6483 7995 8776 9728

4th Prize ₹250/-
0433 0537 2950 4186 4489 4592 4785 5803 9033 9364

5th Prize ₹120/-
0083 0121 0346 0438 0654 0685 0829 0931 1012 1050
1060 1101 1109 1189 1216 1331 1397 1408 1419 1472
1563 1571 1942 2094 2137 2168 2191 2390 2402 2619
2675 2782 2911 3189 3417 3510 3678 3692 3740 3972
4001 4113 4231 4278 4458 4471 4625 4678 4686 4769
4904 5063 5152 5252 5292 5422 5425 5430 5627 5629
5689 5704 5752 5864 5929 5969 5977 6009 6019 6076
6234 6254 7083 7133 7167 7177 7345 7406 7451 7454
7571 7696 8076 8085 8246 8247 8393 8602 8679 8880
8974 9143 9254 9476 9523 9550 9660 9750 9971 9996

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 06:00 PM

DEAR EARTH FRIDAY

Draw No:63 DrawDate on:11/02/22

1st Prize ₹1 Crore/- 77J 66701

Cons. Prize Rs.1000/- 66701 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-
04279 20911 25196 29129 48331 54892 60980 63344 90015 94676

3rd Prize ₹450/-
0505 1800 2298 2300 3133 3250 3845 4207 7326 9090

4th Prize ₹250/-
3568 3825 4251 4617 6342 7342 7647 7812 9068 9197

5th Prize ₹120/-
0112 0283 0402 0494 0530 0597 0796 0908 0955 1022
1038 1155 1291 1368 1461 1505 1606 1678 1891 1976
1978 2166 2207 2318 2552 2613 2642 2703 3028 3101
3201 3252 3368 3373 3385 3402 3531 3819 3939 3952
4028 4044 4358 4438 4465 4655 4784 4867 4882 4926
5030 5103 5112 5142 5418 5436 5480 5540 5630 5636
5789 5891 6045 6236 6245 6300 6445 6576 6749 6831
7302 7356 7522 7606 7653 7671 7673 7683 7972 8166
8188 8542 8550 8638 8659 8669 8697 8821 8875 8988
8994 8996 9142 9344 9673 9680 9789 9848 9889 9995

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES

Draw Time: 04:00 PM

LABHLAXMI SAPPHIRE FRIDAY

Draw No:4 DrawDate on:11/02/22

1st Prize ₹10,000/- 6511

2nd Prize ₹5,000/- 1041
3rd Prize ₹500/- 1864
4th Prize ₹300/- 3308
5th Prize ₹200/- 0083
6th Prize ₹100/-

0059 0079 0090 0109 0143 0197 0205 0236 0251 0256
0259 0344 0367 0384 0395 0423 0442 0460 0473 0497
0513 0532 0593 0604 0607 0625 0637 0639 0646 0649
0675 0694 0808 0812 0818 0836 0845 0862 0890 0965
0971 0991 1040 1052 1058 1115 1197 1372 1459 1502
1518 1562 1569 1624 1689 1712 1732 1751 1753 1761
1789 1792 1830 1831 1855 1902 1904 1906 1936 2047
2048 2052 2057 2058 2084 2099 2113 2150 2170 2177
2221 2244 2339 2348 2355 2441 2445 2464 2472 2496
2522 2532 2622 2623 2677 2689 2693 2720 2730 2751
2761 2832 2873 2900 2907 2946 2996 3020 3066 3138
3171 3176 3185 3222 3238 3245 3264 3287 3289 3291
3312 3349 3352 3433 3448 3482 3487 3524 3609 3695
3705 3723 3755 3781 3798 3799 3810 3814 3826 3900
4041 4161 4186 4201 4240 4297 4314 4350 4398 4416
4419 4431 4512 4540 4544 4558 4570 4602 4607 4644
4648 4659 4699 4710 4752 4761 4762 4773 4796 4797
4826 4838 4845 4868 4871 4952 4966 5010 5057 5072
5087 5154 5173 5196 5203 5224 5263 5264 5272 5301
5309 5312 5365 5373 5376 5425 5444 5476 5548 5562
5641 5695 5706 5709 5813 5846 5886 5915 5939 5978
5980 6052 6061 6070 6079 6084 6094 6128 6145 6165
6205 6219 6229 6233 6324 6401 6443 6449 6463 6466
6478 6479 6517 6527 6530 6558 6572 6583 6599 6631
6640 6686 6701 6706 6712 6713 6726 6757 6761 6763
6813 6826 6830 6832 6858 6868 6877 6878 6938 6949
6955 6981 6990 7008 7015 7033 7073 7074 7076 7089
7113 7124 7126 7128 7159 7172 7254 7255 7278 7315
7318 7335 7362 7388 7443 7450 7496 7498 7510 7522
7524 7584 7585 7638 7680 7702 7720 7746 7773 7812
7837 7838 7916 7931 7967 7978 7993 8067 8073 8086
8112 8117 8147 8157 8217 8329 8334 8337 8359 8372
8394 8435 8464 8485 8487 8499 8512 8545 8548 8570
8677 8685 8701 8711 8717 8740 8754 8777 8800 8806
8818 8845 8861 8887 8895 8906 8916 8968 8970 9016
9029 9058 9128 9152 9157 9182 9200 9219 9252 9281
9290 9294 9383 9397 9411 9420 9433 9453 9495 9497
9502 9518 9541 9544 9547 9550 9552 9665 9668 9683
9708 9734 9752 9760 9819 9840 9842 9858 9871 9992

ISSUED BY : THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES,
GOVERNMENT OF SIKKIM DEORALI - 737102, SIKKIM.
For Results, please visit : www.sikkimlotteries.com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES

Draw Time: 07:00 PM

LABHLAXMI ONYX FRIDAY

Draw No:4 DrawDate on:11/02/22

1st Prize ₹10,000/- 9375

2nd Prize ₹5,000/- 4335
3rd Prize ₹500/- 3080
4th Prize ₹300/- 3306
5th Prize ₹200/- 9024
6th Prize ₹100/-

0004 0044 0054 0089 0090 0121 0144 0171 0176 0185
0224 0225 0239 0244 0246 0248 0255 0346 0370 0396
0407 0415 0470 0472 0543 0557 0587 0603 0622 0674
0710 0733 0804 0842 0872 0898 0904 0909 0944 1038
1082 1115 1121 1128 1160 1202 1241 1274 1276 1277
1310 1315 1328 1338 1351 1444 1504 1507 1552 1577
1612 1613 1623 1625 1645 1653 1678 1682 1713 1725
1776 1840 1859 1932 1942 2016 2080 2089 2164 2180
2227 2265 2296 2299 2399 2452 2453 2477 2480 2531
2583 2588 2664 2698 2703 2747 2760 2761 2764 2772
2779 2891 2896 2897 2901 2920 2933 3038 3044 3059
3137 3197 3199 3232 3236 3241 3265 3291 3297 3373
3397 3402 3425 3428 3436 3454 3469 3481 3485 3489
3589 3634 3659 3668 3708 3710 3757 3770 3823 3824
3865 3868 3965 3967 3989 4002 4011 4041 4084 4104
4122 4195 4199 4203 4220 4225 4234 4246 4294 4298
4329 4346 4353 4367 4393 4430 4436 4441 4463 4503
4512 4517 4518 4525 4553 4555 4556 4588 4631 4664
4700 4726 4754 4769 4788 4828 4847 4874 4885 4910
4958 4979 4993 5054 5064 5153 5192 5200 5218 5219
5224 5231 5244 5262 5274 5283 5344 5355 5411 5413
5445 5492 5504 5554 5672 5715 5744 5760 5774 5817
5866 5875 5887 5927 5976 5982 5993 6030 6058 6097
6167 6181 6194 6201 6228 6247 6267 6297 6309 6318
6320 6331 6359 6411 6427 6429 6431 6432 6474 6476
6491 6523 6573 6626 6649 6652 6655 6664 6680 6683
6715 6742 6753 6780 6783 6785 6807 6848 6872 6901
6931 6941 6948 7006 7013 7031 7042 7104 7120 7140
7157 7175 7196 7278 7293 7304 7308 7344 7379 7403
7442 7456 7492 7505 7601 7695 7730 7762 7769 7817
7823 7836 7838 7864 7905 7918 7931 7976 8032 8053
8077 8079 8093 8094 8097 8123 8143 8194 8211 8213
8219 8245 8290 8305 8322 8330 8371 8373 8380 8388
8392 8401 8402 8439 8463 8477 8488 8512 8535 8575
8579 8596 8616 8619 8671 8774 8815 8838 8839 8941
8949 8975 8986 9054 9057 9157 9190 9192 9205 9218
9219 9225 9226 9247 9289 9293 9323 9328 9343 9350
9363 9379 9417 9435 9437 9626 9629 9655 9666 9679
9745 9768 9782 9791 9876 9882 9903 9915 9987 9991

ISSUED BY : THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES,
GOVERNMENT OF SIKKIM DEORALI - 737102, SIKKIM.
For Results, please visit : www.sikkimlotteries.com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES

Draw Time: 08:00 PM

DEAR 100 OSTRICH FRIDAY

Draw No:4 DrawDate on:11/02/22

1st Prize ₹20LAKHS/- 22487

2nd Prize ₹9000/-
0496 1551 2777 3096 3225 3657 3688 5487 6554 7675

3rd Prize ₹5000/-
0058 0897 1985 2901 3589 3679 4470 7806 7918 8413

4th Prize ₹2000/-
0171 0651 2255 2751 5968 7412 7530 8956 9287 9621

5th Prize ₹1000/-
2944 3978 4086 4387 5035 5091 5993 6644 7416 9826

6th Prize ₹500/-
0038 0212 0346 0642 0653 0728 0768 0822 1159 1434
1444 1482 1571 1607 1644 1910 2052 2095 2192 2333
2439 2488 2559 2632 2687 2734 3065 3076 3347 3379
3424 3468 3547 3610 3691 3850 3890 3912 3970 3980
4029 4486 4603 4679 4728 4758 4776 4785 4788 4948
4984 5087 5145 5613 5945 5950 6061 6148 6444 6600
6634 6643 6681 6792 6901 7045 7065 7166 7192 7195
7203 7445 7657 7666 7736 7939 7959 8083 8199 8277
8425 8469 8608 8640 8671 8724 8761 8771 8815 8820
8906 8919 8957 9082 9257 9263 9409 9540 9632 9742

ISSUED BY : THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES,
GOVERNMENT OF SIKKIM DEORALI - 737102, SIKKIM.
For Results, please visit : www.sikkimlotteries.com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES

Draw Time: 08:00 PM

DEAR 20 FORTNIGHTLY

Draw No:2 DrawDate on:11/02/22

1st Prize ₹10LAKHS/- A 90430

2nd Prize ₹3000/-
0227 0943 2224 3033 4022 4761 5200 7130 8150 9330

3rd Prize ₹1000/-
1218 2504 2960 4723 5724 7572 8052 8395 9101 9377

4th Prize ₹500/-
0706 0841 2000 2720 2889 6139 6404 6963 7594 7800

5th Prize ₹100/-
3084 3534 3899 5028 5993 7317 7558 7824 8795 9365

6th Prize ₹50/-
0122 0436 0819 0920 0940 1004 1081 1095 1143 1359
1372 1413 1529 1723 1834 1998 2035 2170 2200 2300
2348 2418 2500 2547 2581 2604 2739 2801 2841 2870
2900 2936 3143 3223 3356 3584 3632 3645 3715 3771
3862 4061 4125 4126 4158 4300 4468 4608 4743 5117
5259 5422 5490 5555 5718 5799 5917 6127 6171 6249
6304 6511 6538 6771 6827 6935 7023 7149 7255 7282
7302 7326 7427 7448 7555 7624 7670 7671 7958 8082
8090 8206 8232 8424 8467 8519 8575 8593 8768 8774
8784 8818 8937 9102 9189 9232 9482 9583 9637 9746

ISSUED BY : THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES,
GOVERNMENT OF SIKKIM DEORALI - 737102, SIKKIM.
For Results, please visit : www.sikkimlotteries.com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

दिल्ली विश्वविद्यालय

विज्ञापन सं. Estab.IV/292/2022 दिनांक:17.01.2022

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में, 7वां केन्द्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के 13ए पे स्तर शैक्षिक में, सहयोगी प्रोफेसर के पद की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन फार्म में आनलाइन आवेदनों को आमंत्रित किया जाता है। आवेदन के प्राप्ति की अंतिम तिथि 31.03.2022 अथवा रोजगार समाचार मे विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह है, जो भी बाद मे हो। विस्तृत विवरण के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.du.ac.in** देखें एवं 'डीयू के साथ वर्क' शीर्षक अन्तर्गत 'नौकरी एवं अवसर' पर क्लिक करें।

कोई भी बदलाव/संशोधन केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही अंकित किया जाएगा।

davp 21231/12/0007/2122 **पंजीयक**

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
भारत सरकार के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय
कोर-5ए, तृतीय-पंचम तल, भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त छमाही हेतु वित्तीय परिणाम की सीमित समीक्षा (₹ लाख में)

विवरण	31.12.2021 को समाप्त छमाही	31.12.2020 को समाप्त छमाही	31.06.2021 को समाप्त वित्त वर्ष
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखा परीक्षित
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	**2,20,124.95**	**2,59,647.42**	**4,82,735.24**
(क) अग्रिमों पर ब्याज	2,09,221.90	2,44,153.06	4,58,633.62
(ख) निवेशों पर आय	9,033.84	7,629.54	14,343.04
(ग) बैंक जमाओं पर ब्याज	1,869.21	7,864.82	9,758.58
(घ) अन्य	-	-	-
2. अन्य आय	**46,640.11**	**2,363.32**	**5,084.40**
3. कुल आय (1+2)	**2,66,765.06**	**2,62,010.74**	**4,87,819.64**
4. व्यय किया गया ब्याज	**1,63,240.54**	**1,84,068.19**	**3,57,380.91**
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	**7,330.40**	**3,481.99**	**8,111.50**
(i) कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	1,737.23	1,409.98	3,750.15
(ii) अन्य परिचालन व्यय (क)+(ख)+(ग)	5,593.17	2,072.01	4,361.35
(क) ब्रोकरेज, गारंटी शुल्क एवं अन्य वित्त प्रभार	157.09	186.85	346.98
(ख) उधारों पर स्टांप शुल्क	10.37	5.02	54.17
(ग) अन्य व्यय	5,425.71	1,880.14	3,960.20
6. विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण (लाभ)/हानि	**(951.09)**	**4,390.74**	**6,078.12**
7. प्रावधान एवं आकस्मिक व्ययों को छोड़कर कुल व्यय (4+5+6)	**1,69,619.85**	**1,91,940.92**	**3,71,570.53**
8. प्रावधान एंव आकस्मिक व्ययों से पूर्व परिचालन लाभ (3-7)	**97,145.21**	**70,069.82**	**1,16,249.11**
9. कर एवं आकस्मिक व्ययों के अलावा अन्य प्रावधान	(97,095.78)	60,364.78	70,252.38
10. असामान्य मदें	-	-	-
11. कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (+)/ हानि (–) (8–9–10)	**1,94,240.99**	**9,705.04**	**45,996.73**
12. कर व्यय	48,900.00	18,100.00	(20,315.75)
13. कर के पश्चात सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ (+)/ हानि (–) (11–12)	**1,45,340.99**	**(8,394.96)**	**66,312.48**
14. असाधारण मदें (कर व्यय का निवल)	-	-	-
15. अवधि हेतु निवल लाभ (+)/ हानि (–) (13–14)	**1,45,340.99**	**(8,394.96)**	**66,312.48**
16. चुकता पूंजी (भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में)	1,45,000.00	1,45,000.00	1,45,000.00
17. पुनर्मूल्यांकन भंडार को छोड़कर भंडार (पिछले लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार)	8,34,501.57	7,67,936.64	8,34,501.57
18. विश्लेषणात्मक अनुपात:			
(i) पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात	15.53%	12.56%	12.14%
(ii) प्रति शेयर आय (ईपीएस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
19. एनपीए अनुपात			
क) सकल एनपीए की राशि	1,53,510.38	2,50,284.59	2,50,284.59
ख) निवल एनपीए की राशि	-	-	-
ग) सकल एनपीए का %	2.11%	3.18%	2.91%
घ) निवल एनपीए का %	-	-	-
ङ) आस्तियों पर लाभ (वार्षिक)	3.46%	(0.19)%	0.75%

टिप्पणी:

1. उपरोक्त परिणाम लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षित एवं 11 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।
2. डीएचएफएल खाते के समाधान के तहत, बैंक को पीरामल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ₹ 1,054.88 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। राशि को ₹ 86 करोड़ के ब्याज और शेष ₹ 968 करोड़ के मूल बकाया के बीच प्रभाजित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप किये गए एनपीए प्रावधान को वापस ले लिया गया है।
3. 1991–92 घोटाले के मामले में बैंक को अभिरक्षक से ₹ 523.18 करोड़ (ब्याज के साथ दावा राशि) भी प्राप्त हुए। इसमें से बैंक ने ₹ 428.98 करोड़ की ब्याज राशि अन्य आय (एकमुश्त असाधारण मद) के रूप मे बुक की थी। चूंकि बैंक ने अभिरक्षक को वचनपत्र दिया है, अतः राशि को आकस्मिक देयता के रूप में चिन्हित किया गया है।
4. भारतीय रिजर्व बैंक के 04 अगस्त, 2016 के परिपत्र के अनुसार, बैंक निरंतर प्रोफार्मा आईएनडी एएस विवरणी तैयार कर रहा है और नियमित रूप से विनियामक को प्रस्तुत कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से यह सलाह दी है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।
5. जहां आवश्यक था वहां पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत /पुनः व्यवस्थित किया गया है।

ह/–
एस. के. होता
प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 फरवरी, 2022

ह/–
(सी ए सिद्धार्थ बंसल)
भागीदार
सदस्यता सं. 518004

सम तारीख की हमारी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार
कृते बंसल एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 0001113 एन/एन 500079

davp 62102/12/0002/2122

बेकाबू ना हो महंगाई

रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। यह लगातार दसवां मौका है, जब दरें जस की तस रखी गईं। आखिरी बार 22 मई 2020 को पॉलिसी रेट में बदलाव हुआ था। तब ब्याज दरें घटाई गई थीं। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को उधार देता है, उस रेपो रेट को 4 फीसदी पर बनाए रखा गया। आरबीआई के पास पैसा जमा करने पर बैंकों को मिलने वाली ब्याज दर यानी रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 फीसदी पर रहने दिया गया। अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में 0.15-0.40 फीसदी तक बढ़ोतरी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रिजर्व बैंक के दरों में बदलाव ना करने की वजह यह है कि वह इकॉनमिक रिकवरी को सपोर्ट देना चाहता है। इससे पहले बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। केंद्र को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी कंस्यूमर डिमांड कमजोर है। इस वजह से निजी क्षेत्र की ओर से बहुत निवेश नहीं हो रहा। सरकार को लगता है कि उसके अधिक पैसा खर्च करने से आर्थिक विकास दर में तेजी आएगी। लिहाजा रोजगार बढ़ेगा और लोग अधिक पैसा खर्च करेंगे। इससे डिमांड की दिक्कत दूर हो सकती है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव ना करके एक तरह से सरकार की इस नीति को समर्थन दिया है।

इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि जब तक ग्रोथ टिकाऊ नहीं हो जाती, तब तक वह कर्ज महंगा नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक पेच है। देश में महंगाई बढ़ रही है। खुदरा महंगाई दर भले ही रिजर्व बैंक के 6 फीसदी की अधिकतम सीमा से कम हो, लेकिन थोक महंगाई दर बहुत ऊंची है। इससे खुदरा महंगाई दर आने वाले वक्त में बढ़ेगी। इस बीच, कच्चे तेल के दाम में काफी बढ़ोतरी हुई है। यूं तो पांच राज्यों में चुनाव को देखते हुए तीन महीने से अधिक वक्त से देश में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन यह स्थिति चुनाव खत्म होने के बाद बदल सकती है। तब तेल की कीमतों का असर भी महंगाई पर पड़ेगा। उधर, अमेरिका में महंगाई दर 7 फीसदी के करीब पहुंच गई है, जो 80 के दशक की शुरुआत के बाद सबसे ज्यादा है। इसलिए वहां मार्च से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसी वजह से भारतीय शेयर बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशक कुछ महीनों से पैसा निकाल रहे हैं। रिजर्व बैंक को यह पक्का करना होगा कि इससे रुपया कमजोर ना हो। यह भी देखना होगा कि सस्ती ब्याज दरों की वजह से किसी भी एसेट क्लास में बुलबुला ना बने और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई बेकाबू ना हो क्योंकि वह खासतौर पर गरीबों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है।

संपादकीय पृष्ठ

श्रम बिकाऊ है, शरीर नहीं

तस्लीमा नसरीन

एक स्वस्थ समाज वह है, जहां तर्क-वितर्क की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाता है। तर्क-वितर्क को प्रोत्साहित किया जाता है, और समाज के लोग इनमें सहभागिता करते हैं, तो मस्तिष्क सक्रिय होता है। ऐसे में, दुविधाग्रस्त लोग भी उनके साथ खड़े होने का साहस दिखाते हैं, जिनके तर्क में दम होता है। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारा समाज तर्क-वितर्क को अच्छा नहीं मानता। वह अक्सर बगैर तर्क-वितर्क के उस पक्ष को सही मान लेने का अभ्यस्त हो चुका है, जो पक्ष बड़ा और प्रतिष्ठित होता है तथा जिसके पक्ष में अधिकांश लोग खड़े होते हैं।

पुराने जमाने से आज तक यही चलन बना हुआ है कि जो व्यक्ति भीड़ से अलग खड़ा होता है, जो आदमी बहुमत से भिन्न विचार व्यक्त करता है, उसे विवादास्पद और गलत बता दिया जाता है। मनुष्य बहुमत से अलग विचार से डरता है, कोई खुद को विवादास्पद नहीं बनाना चाहता।

यह स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है, यह तो एक बंद जलाशय की तरह है। मैं जब बहुमत से अलग विचार व्यक्त करती हूं, तो समाज के सभी स्तरों के लोग मुझे निशाना बनाते हैं। विवादास्पद बताकर वे मुझे दूसरों से अलग करते हैं। जैसे, समाज किसी का हुक्का-पानी बंद कर देता है, वैसी ही स्थिति मेरी है।

भारत का समाज बांग्लादेश के समाज से बहुत अलग नहीं है। धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने पर यहां भी लोग मुझे अजीब निगाहों से देखते हैं। बांग्लादेश ने मुझे जिस तरह अपने से अलग कर दिया है, भारत में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है। कुछ ही दिनों पहले मैंने सरोगेसी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। चूंकि मेरे विचार प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विचार से नहीं मिलते, इसलिए लोगों ने मुझे निशाना बनाना शुरू कर दिया। सरोगेसी पर समाज का बहुमत यह है कि धनी और व्यस्त महिलाएं अगर पैसे देकर गरीब महिलाओं की कोख किराये पर लेती हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

इससे जहां धनी महिलाओं की इच्छा पूरी हो जाती है, वहीं गरीब महिलाओं को भी अपनी कोख किराये पर देने की अच्छी-खासी कीमत मिल जाती है। लेकिन मैं सरोगेसी का समर्थन नहीं करती। मेरा मानना यह है कि किसी के शरीर की बिक्री नहीं की जा सकती, किराया चुकाकर उसके शरीर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। श्रम बिकाऊ है, शरीर नहीं। भारत में सरोगेसी के जरिये संतान प्राप्त करना कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड की नायिकाओं या नायकों की स्त्रियों द्वारा सरोगेसी के माध्यम से संतान प्राप्त करने की सूचनाएं जब-तब आती रहती हैं। यहां तक कि दूसरे धनी देशों से भी लोग भारत में गरीब महिलाओं की कोख किराये पर लेने आते हैं। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। मैं मानती हूं कि सरोगेसी एक चमत्कारिक वैज्ञानिक आविष्कार है। लेकिन सरोगेसी का चलन तभी तक रहेगा, जब तक दुनिया में गरीबी रहेगी। धनी लोग नौ महीने के लिए गरीब महिलाओं की कोख किराये पर लेते हैं।

दूसरी तरफ कभी कोई धनी महिला अपनी कोख किराये पर नहीं देगी, क्योंकि गर्भावस्था के तमाम जोखिम होते हैं, शिशु के जन्म के समय भी खतरा कोई कम नहीं रहता। जाहिर है, दरिद्रता के कारण ही गरीब महिलाएं जान-बूझकर यह जोखिम उठाती हैं। धनी महिलाएं ऐसा जोखिम भला क्यों उठाना चाहेंगी? गरीब महिलाएं या उनका परिवार भी विवश होकर ही ऐसा जोखिम उठाता है। और यह भी तय है कि हर गरीब महिला यह जोखिम नहीं उठाती। धनी और व्यस्त महिलाओं को अगर बच्चे ही चाहिए, तो वे अनाथ बच्चों को गोद ले सकती हैं। आखिर अनाथ बच्चों को गोद लेने का चलन दुनिया भर में है ही। लेकिन नहीं, सरोगेसी की इच्छुक महिलाएं अपने जीन के साथ रेडिमेड बच्चा चाहती हैं।

सरोगेसी का समर्थन मैं तभी करूंगी, जब सिर्फ दरिद्र स्त्रियां ही नहीं, बल्कि धनी महिलाएं भी दूसरों को अपना कोख इस्तेमाल करने देंगी, पैसों के लिए नहीं, बल्कि उन महिलाओं की मदद करने के लिए, जो संतान जन्म देने में अक्षम हैं।

सरोगेसी एक अद्भुत वैज्ञानिक आविष्कार है, लेकिन सिर्फ गरीब महिलाओं की कोख ही इसकी प्रयोगशाला क्यों बने? इसी तरह मैं बुर्के को भी मान लूंगी, लेकिन तब, जब पुरुष भी बुर्का पहनेंगे। ऐसे ही वेश्यालयों का समर्थन करूंगी, जब जगह-जगह पुरुष वेश्यालय भी खुलें। ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब यही है कि सरोगेसी, बुर्का और वेश्यालय वस्तुत: स्त्रियों और गरीबों के शोषण के ही औजार हैं।

मैंने जैसे ही सरोगेसी के खिलाफ अपना मत व्यक्त किया, समाज के बंद जलाशय से मानो लहरें उठने लगीं। चूंकि पितृसत्तात्मक समाज स्त्री के शरीर को बिकाऊ समझता है, इसलिए वह सरोगेसी को अनुचित नहीं मानता। समाज का मानना है कि धनी महिलाओं को कोख किराये पर लेने का अधिकार होना चाहिए। कोई उस दरिद्र स्त्री के बारे में नहीं सोचता, जो सिर्फ पैसे के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाती है। सरोगेसी के समर्थकों का कहना है कि कोख किराये पर लेने का अच्छा-खासा पैसा दिया जाता है। यह समृद्ध समाज का वही पुराना तर्क है, जिसके तहत गरीब अगर पैसों के बदले जीवन का जोखिम उठाते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत या अनैतिक नहीं है। हालांकि जो समाज वेश्यालय का समर्थन करता है, वह समाज किराये की कोख का भी समर्थन करेगा ही। कुछ लोग सरोगेसी को उचित ठहराने के लिए कहते हैं कि गरीब महिलाएं ही पैसे के लिए अपनी कोख किराये पर देती हैं, उनसे जबर्दस्ती नहीं की जाती। पैसे के लिए अपना शरीर बेचने वाली महिलाओं के बारे में भी यही कहा जाता है कि वे अपनी इच्छा से ऐसा करती हैं। यह कुतर्क है।

सच्चाई यह है कि कोई महिला अपना शरीर या अपनी कोख विवशता में ही बेचती हैं। मीडिया का कहना है कि चूंकि बॉलीवुड की नायिका प्रियंका चोपड़ा ने सरोगेसी के जरिये संतान जन्म दिया है, इसलिए सरोगेसी के खिलाफ विचार व्यक्त कर दरअसल मैंने उन्हें निशाना बनाया है। ऐसा कतई नहीं है। मैं समाज में व्याप्त प्रवृत्तियों के खिलाफ बोलती-लिखती हूं, किसी व्यक्ति को निशाना बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए खुद पर होते हमले से भी मैं असहज नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि एक दिन इस दुनिया में ऐसी समानता आए कि पैसे के लिए किसी गरीब महिला को अपना शरीर या अपनी कोख बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।

भारत के रुख पर लगने लगे कयास

संदीप त्रिपाठी

सदियों से रूसी साम्राज्य और बाद में सोवियत संघ ने विश्व राजनीति की परिधि एवं केंद्र के बीच हमेशा खुद को झुलते हुए पाया। फिर से रूस विश्व राजनीति में विवाद का केंद्र बन गया है। रूस-यूक्रेन गतिरोध को लेकर जारी तनाव के बीच भारत के रुख को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। लंबे समय तक चुप रहने के बाद नई दिल्ली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन मामले में रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग रखा। इसके साथ नई दिल्ली ने शांतिपूर्ण बातचीत के जरिये तनाव को तत्काल कम करने की अपील की।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने स्पष्ट किया, 'भारत का हित एक ऐसा समाधान खोजने में है, जो सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को तत्काल कम कर सके और इसका उद्देश्य क्षेत्र और उससे बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता हासिल करना है।' रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'वोट से पहले अमेरिकी दबाव के आगे न झुकने' के भारतीय कदम को 'साहसिक' बताया। हालांकि अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी खेमे ने भारत के रुख पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वर्ष 2014 में भी नई दिल्ली ने इसी तरह रूसी हित का हवाला देकर खुद को वोटिंग से अलग रखा था। तब क्रीमिया मुद्दे पर भी पुतिन ने भारत के 'संयम और निष्पक्षता' की सराहना की थी।

मास्को ने भारत के रुख की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देश अन्य देशों के 'घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने' के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन मामले में रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की पश्चिमी देशों की धमकियों के बीच भारत ने स्पष्ट कहा है कि 'वह रूस के खिलाफ किसी भी आर्थिक प्रतिबंध का पक्षकार नहीं बन सकता।' भारत का बयान मास्को के साथ करीबी गठबंधन का प्रमाण है। सभी पक्षों के वैध सुरक्षा हितों के उल्लेख का मतलब यह था कि मास्को को अपने निकट पड़ोस में नाटो की उपस्थिति को लेकर गहरी सुरक्षा चिंताएं थीं। इसके अलावा, नई दिल्ली ने पूरे बयान में यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैन्य जमावड़े के बारे में उल्लेख नहीं किया। इसे अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो और यूक्रेन को मौजूदा संकट के लिए कारक के रूप में उद्धृत किया गया है।

रूस भारत के लिए क्यों मायने रखता है? असल में नई दिल्ली मास्को के साथ अपने विश्वसनीय और वर्षों से परखी हुई साझेदारी को खतरे में नहीं डालना चाहता। भारत की सैन्य आपूर्ति का लगभग 60 प्रतिशत रूस निर्मित है। साफ है कि मास्को को अलग-थलग करने का जोखिम भारत नहीं उठा सकता है, खासकर तब, जब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पूर्वी सीमा पर गतिरोध बना हुआ है। नई दिल्ली की रणनीतिक गणना यह संकेत देती है कि वह रूस के आंतरिक मामलों में संलिप्त नहीं होना चाहती। बदले हुए भू-राजनीतिक माहौल में मास्को और नई दिल्ली ने अपनी-अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाई है। दोनों ने विश्व मंचों पर क्षेत्रीय अखंडता और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सोवियत संघ के दौरान भारत और रूस, जो कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताता था, की दोस्ती अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अभूतपूर्व थी। बेशक अब समय बदल गया है। दोनों देश अपने-अपने सामरिक मुद्दों को नई वास्तविकताओं के अनुसार चला रहे हैं। पुरानी कहावत अब भी याद दिलाती है कि कोई स्थायी मित्र नहीं होता, केवल हित स्थायी होते हैं। साझा सुरक्षा चिंताओं ने दोनों देशों को जोड़ा था और भविष्य में भी दोनों को करीब ला सकता है। भारत ने अपनी सेना के लिए एके-203 राइफल बनाने के लिए रूस के साथ 60 करोड़ डॉलर के संयुक्त उद्यम समझौता किया है। इन सौदों के साथ रूस भारत के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में शीर्ष पर है। दोनों देश एक और दशक के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते का विस्तार करना चाहते हैं, जो अमेरिका को संभवत: अच्छा नहीं लगेगा। इस पृष्ठभूमि में नई दिल्ली ने हाल के दिनों में संयुक्त राष्ट्र में कई बार रूस के साथ गठबंधन कर मतदान किया है। नए भू-राजनीतिक रुझानों को समझने के लिए दोनों पक्षों द्वारा अभी व्यावहारिक लचीलेपन का आनंद लिया जा रहा है।

पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस आर्थिक और सैन्य स्तर पर चीन के करीब चला गया है। उसी तरह, क्वाड के माध्यम से भारत की संलग्नता किसी भी तरह से रूस की तरफ नहीं है, बल्कि चीन के मुखर और व्यापक हितों के खिलाफ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए है। नई दिल्ली द्वारा 'शांतिपूर्ण समाधान' का आह्वान चीन-पाकिस्तान-रूस के उभरते त्रिकोण को कमजोर करने के लिए एक और दांव होगा। हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बढ़ती प्रमुखता के कारण मास्को और नई दिल्ली के बीच मतभेदों की एक शृंखला उभरी। नई दिल्ली का मानना है कि चीनी खेमे की तुलना में मास्को को अपने खेमे में रखना बेहतर है। रूस ने न केवल क्षेत्रीय, बल्कि वैश्विक मामलों में भी भारत के उदय और महत्व को स्वीकार किया है।

रूस की मुख्य सुरक्षा चिंता के यथार्थवादी विचारक जबिग्न्यू ब्रजेजिस्की यूक्रेन के भू-राजनीतिक दबदबे को निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित करते हैं : यूक्रेन के बिना रूस एक साम्राज्य नहीं रह जाता है, जबकि यूक्रेन को मिलाकर वह स्वत: एक साम्राज्य बन जाता है। पूर्व सोवियत संघ के अन्य गणराज्यों के विपरीत यूक्रेन मास्को के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 5.2 करोड़ की आबादी के साथ एक स्वतंत्र यूक्रेन का उदय सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटनाओं में से एक था और रूसी राजनीतिक इतिहास में एक राष्ट्रीय त्रासदी माना जाता था। यूक्रेन हमेशा से एक महत्वपूर्ण देश रहा है, और अब भी है : पहला, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, और दूसरा, रूसी संघ के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों के कारण।

नाटो के पूर्व की ओर विस्तार से रूस के मुख्य रणनीतिक हितों को खतरा है, जो नाटो और रूसी संघ के बीच विवाद का विषय है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बार-बार आरोप लगाया है कि पश्चिम ने हमसे कई बार झूठ बोला है, पीठ पीछे फैसले लिए हैं। यह नाटो के पूर्व में विस्तार के साथ हुआ है। साफ है कि रूस की भू-रणनीतिक अस्थिर स्थिति ने रूसी नीति-निर्माताओं के लिए सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है।

असंभव वादों का पिटारा

प्रमोद भार्गव

उत्तर-प्रदेश में चुनाव प्रचार बंद होने के ठीक पहले यहां के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दल भाजपा ने संकल्प-पत्र और सपा ने वचन-पत्र के जरिए मतदाताओं को लुभाने के लिए असंभव वादों का पिटारा खोल दिया है।

भाजपा ने होली-दीवाली पर दो गैस सिलेंडर, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सरकारी बस में मुफ्त यात्रा, प्रावीण्य सूची में आने वाली छात्राओं को स्कूटी और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली एवं गन्ना भुगतान में 14 दिन से ज्यादा देरी होने पर चीनी मिलों से ब्याज दिलाने का वचन दिया है।

यही नहीं, यह पहली बार देखने में आया है कि भाजपा ने कानूनी वादे की घोषणा कर लव-जिहाद कानून के तहत 10 साल की कैद और 1 लाख रु पये जुर्माने का भी वचन दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने 88 पृष्ठीय, समाजवादी वचन-पत्र में पांच साल में एक करोड़ नौकरी, दो गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली, बारहवीं पास को लैपटॉप, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा व नौकरी में 33 प्रतिषत आरक्षण और किसान आंदोलन में मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रु पए देने का वादा किया है। किसानों को हर साल दो बोरी डीएपी खाद एवं यूरिया की पांच बोरी मुफ्त देने के साथ, सभी प्रकार की फसलों पर एमएसपी निष्चित करने और गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिन में भुगतान करने की भीष्म प्रतिज्ञा की है। यही नहीं, सपा आम आदमी के दो पहिया वाहनों को हर माह एक लीटर, ऑटो चालकों को तीन लीटर पेट्रोल या 6 किलो सीएनजी भी देगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इसी तरह के बढ़-चढ़कर वादे अपने-अपने घोषणा-पत्रों में कर चुके हैं। बहरहाल पांचों राज्यों में सभी राजनीतिक दलों ने घोषणाओं का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि जीवन गुजर जाए, तब भी वादे पूरे होने वाले नहीं हैं। अतएव मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाने वाले ये असंभव वादे आखिरकार निराशा ही पैदा करेंगे।

रियासत की इतनी रेबड़ियां बांटी हैं कि मामूली समझ रखने वाला नागरिक भी इन वादों पर भरोसा करने वाला नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवाओं को रोजगार देने के पुख्ता उपाय और सरंचनागत विकास का ढांचा खड़ा करने के वादों की बजाय, ऐसे कार्यों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोलने की बात कही गई है, जिसके कारण देश व राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि वाहनों को मुफ्त ईधन देंगे तो आयात की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, जो विदेशी मुद्रा के लिए संकट बनेगी। इन अफलातूनी घोषणाओं के चलते मुफ्त योजनाओं के बजट का आकार नियमित बजट के आकार से बड़ा होता जा रहा है। बावजूद इसमें कोई दो राय नहीं कि यह भ्रष्ट आचरण नहीं है, लेकिन यह चुनावों की निष्पक्षता को जरूर प्रभावित करता है। जरूरतमंद गरीबों को निशुल्क राशन बिजली, पानी और दवा देने में किसी को कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन वोट पाने के लिए पल्रोभन देना मतदाता को लालची बनाने का काम तो करता ही है, व्यक्ति को आलसी एवं परावलंबी बनाने का काम भी करता है। हालांकि अब मतदाता इतना जागरूक हो गया है कि वह वादों के खोखले वचन-पत्रों के आधार पर मतदान नहीं करता? यदि भाजपा के 2017 विधानसभा चुनाव के वचनों की बात करें तो वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। 14 दिन में किसानों को गन्ना राशि के भुगतान का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। छह इलाकों में फूड पार्क बनाने का वादा भी अधूरा है। सपा ने जो असंभव वादे किए हैं, उनकी बात तो छोड़िए जब वह उत्तर-प्रदेश की सत्ता में थी, तब मुफ्त डीजल-पेट्रोल तो क्या बालिकाओं को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से भी कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में भी सपा पिछड़ी रही। इसी तरह कांग्रेस का घोषणा-पत्र लोक-लुभावन वादों से भरा है। छात्राओं को स्कूटी, महिलाओं को गैस सिलेंडर, पुलिस में महिलाओं की भर्ती का प्रतिशत बढ़ाने और तीन नई महिला बटालियन खड़ी करने के अलावा उत्तर-प्रदेश की लोकसेवा आयोग की परीक्षा समेत अन्य सभी परीक्षाओं में महिलाओं की भागीदारी 25 प्रतिशत करने का वादा किया है, लेकिन हकीकत में कांग्रेस और बसपा चुनावी परिदृश्य से लगभग बाहर हैं। सभी राजनीतिक दलों ने हर साल करोड़ों नये रोजगार देने के वादे तो किए हैं, लेकिन रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, इसका कोई हवाला दृष्टि-पत्रों में नहीं है। दरअसल, हमारे यहां केंद्र की सरकार हो अथवा राज्य सरकार ईमानदारी से रोजगार के अवसर पैदा करने के उपाय किए ही नहीं किए गए हैं।

इस बहाने प्राकृतिक संपदा के दोहन का सिलसिला तेज करने की जरूर कोशिशें की जाती रही हैं, जबकि हकीकत हैं कि अंतत: आधुनिक और औद्योगिक विकास का पूरा अजेंडा कृषि और खनिज पर टिका है, परंतु विडंबना देखने में आ रही है कि खेती घाटे का सौदा हो गया है और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि मुफ्त उपहार बांटे जाने के वादे राज्यों की आर्थिक बदहाली का सबब बन रहे हैं। मतदाता को ललचाने के ये अतिवादी वादे, घूसखेरी के दायरे में आने के साथ, मतदाता को भरमाने का काम भी करते हैं। लिहाजा ये आचार संहिता का खुला उल्लघंन हैं। मुफ्तखोरी की आदत डालकर एक बार चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन इससे राज्य और देश का स्थाई रूप से भला होने वाला नहीं है।

कम पानी में भी हो सकती है धान की अच्छी पैदावार

सूखा प्रतिरोधी धान की खेती करना अब मुमकिन हो गया है। शुक्र है कि गेहूं की तरह अब चावल उगाने के लिए तकनीक उपलब्ध हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि धान के खेत को हमेशा पानी से भरा हुआ रखे बिना भी इसकी खेती की जा सकती है। नई तकनीक से धान की फसल के लिए पानी की जरूरत में 40 से 50 फीसदी तक कम करने में मदद मिलेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और फिलिपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) ने संयुक्त रूप से यह तकनीक विकसित की है। इस परियोजना में कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) की भी भागीदारी है। कटक स्थित संस्थान ने ही धान की वैसी किस्मों की पहचान की है जिन्हें दूसरी फसलों की तरह कुछ दौर की सिंचाई के जरिए उगाया जा सकता है। इसने ऐसी कृषि पध्दतियों की भी खोज की है जिसके जरिए धान की ऐसी किस्मों से करीब-करीब उतनी उपज हो सकती है जितनी सामान्य तौर से ज्यादा पैदावार वाली धान की होती है। तकनीकी तौर पर यह एरोबिक राइस कल्टिवेशन कहलाता है। इस तकनीक में धान के खेत में स्थिर पानी की जरूरत नहीं होती और न ही धान के छोटे पौधे तैयार करने की आवश्यकता होती है जैसा कि आम तौर पर होता है और बाद में उसे उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। इस तकनीक में कुशलता से तैयार किए गए खेतों में सीधे बीज बो दिए जाते हैं और इस तरह श्रम लागत की भी बचत हो जाती है।

सीआरआरआई के निदेशक टी. के. आद्या के मुताबिक, एपो नाम के ब्राजील के एरोबिक राइस को दुनिया के सबसे अच्छा एरोबिक राइस माना जाता है। एपो को भारतीय धान के साथ क्रॉसब्रीड करवाकर ऐसी किस्म तैयार की जा रही है जो भारतीय कृषि की पारिस्थितिकी के लिए उपयुक्त हो। इन किस्मों में 40 फीसदी कम पानी का इस्तेमाल होता है और अच्छे प्रबंधन के जरिए यह 4-5 टन धान की उपज हो सकती है। एरोबिक स्थितियों में (बिना स्थिर पानी के) उगाए जाने वाले धान की पैदावार सामान्य तौर पर प्रति हेक्टेयर दो टन से कम होती है। एपो जर्मप्लाज्म समेत एरोबिक धान तैयार करने की लिए ब्रीडिंग सामग्री आरआरआरआई से प्राप्त की गई थी। नई किस्मों से कई का परीक्षण खेत में किया जा चुका है। इनमें से एक किस्म शहभागी धान आईआरआरआई इंडिया सीआरआरआई ब्रीडिंग नेटवर्क के जरिए पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है ताकि सूखा प्रभावित इलाकों में इसकी खेती हो सके। एक किलोग्राम धान के उत्पादन में सामान्यतः तीन से पांच हजार लीटर पानी की दरकार होती है।

सीआरआरआई के क्रॉप प्रॉडक्शन डिवीजन के प्रमुख के. एस. राव कहते हैं कि धान की खेती में ऐसे अपव्ययी तरीके से पानी का इस्तेमाल टिकाऊ नहीं होता है।

आईआरआरआई के मुताबिक, धान की खेती में पानी का इस्तेमाल अगर वैश्विक स्तर पर 10 फीसदी कम कर दिया जाए तो गैर-कृषि की जरूरतों के लिए 150 अरब क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध हो सकता है। हालांकि एरोबिक राइस कल्टिवेशन में कुछ निश्चित तकनीकी समस्याएं हैं जिनसे उबरने के लिए खास कदमों की दरकार है। ऐसी ही एक समस्या है बिना खेतों में भरपूर पानी पहुंचाए बोआई करने के बाद प्रचुरता से उग आए खरपतवार। ये खरपतवार वहां मौजूद पोषक तत्त्व का उपभोग करने में फसलों से होड़ लेते हैं और इस तरह से फसलों को पर्याप्त पोषण से वंचित कर देते हैं। फसलों के विकास के शुरुआती 30 दिन की अवधि में यह समस्या खास तौर पर ज्यादा गंभीर होती है। सीआरआरआई वैज्ञानिकों ने खरपतवार के नाश के लिए रसायन इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। दूसरी मुख्य समस्या लौह की कमी की है। जब वहां स्थिर पानी नहीं होता है तो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन मिट्टी में उपलब्ध लौह का ऑक्सीजनीकरण कर देती है जिससे लौह पौधों के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। यह फसलों की उत्पादकता में कमी ला देता है। इससे निपटने के लिए विशेषज्ञ मिट्टी में आयरन सल्फेट मिलाने की सलाह देते हैं। एरोबिक राइस कल्टिवेशन की बाबत किए गए प्रयोग से जाहिर हुआ है कि बेहतर परिणाम तभी सामने आता है जब लेजर लैंड लेवलिंग मशीन के जरिए खेत को जोता और समतल किया जाता है। इसके साथ ही सीड ड्रिल मशीन की मदद से बीज बोने की दरकार होती है। पर्याप्त दूरी और गहराई के साथ-साथ एक सीध में बीज बोने के लिए मशीन पहले ही विकसित किए जा चुकेहैं। इसे बैल, ट्रैक्टर या पावर ट्रिल के जरिए संचालित किया जा सकता है। बीज बोने में मशीन के इस्तेमाल से कई फायदे मिलते हैं, जिनमें बीजों की बचत, प्रति हेक्टेयर ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाना, खरपतवार में कम से कम लागत और बेहतर उत्पादन शामिल हैं।

कम बारिश या सिंचाई के लिए अपर्याप्त जल की उपलब्धता से पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से बचाने में एरोबिक राइस कल्टिवेशन काफी सहायक हो सकता है। यह वैसे इलाकों के लिए भी खासा उपयोगी हो सकता है जहां भूमिगत जल में एक साथ कई फसलें उगाई जाती है मसलन पंजाब के उत्तरी पश्चिमी इलाके, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही दक्षिण के कुछ इलाके। अन्यथा ज्यादा दोहन के चलते गिर रहे भूजल स्तर को बचाने के लिए उन इलाकों में धान की खेती त्याग दी जानी चाहिए।

टैंसो मीटर से धान की खेती में पानी की बचत

पंजाब एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी ने एक ऐसा ही मीटर तैयार कर लिया है जो किसानों को बताएगा कि खेत को कब कितना पानी चाहिए। यह मीटर है टैंसो मीटर, जो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी महज 300 रुपये में किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मीटर के उपयोग से किसान 25 से 30 फीसदी तक पानी की बचत कर सकते हैं। यूनीवर्सिटी के मिट्टी व भू विभाग के प्रमुख डॉ. अजमेर सिंह सिद्धू के मुताबिक टेंसो मीटर एक छोटा सा पाइपनुमा मीटर है। इसे 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन में गाड़ दिया जाता है। पाइप के एक सिर पर पोरस कप नाम का उपकरण लगाया जाता है। पाइप पर हरे व पीले रंग की पट्टी हैं। पानी का स्तर जब दोनों पट्टियों के बीच में होता है तो किसान को यह संकेत मिल जाता है कि खेत में पानी की कमी है। उसे बेवजह पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

धान उत्पादक राज्यों में किसानों को अच्छी फसल उगाने के लिए खेत में पर्याप्त पानी भरा रखना जरूरी होता है। जबकि पानी की कमी के कारण इसमें मुश्किलें आ रही हैं। धान उगाने के लिए सिंचाई के पानी पर किसानों को काफी खर्च करना पड़ता है। आवश्यकता से ज्यादा पानी खेत में होने से न सिर्फ किसानों की लागत बढ़ जाती है बल्कि पानी का बर्बादी भी होती है। पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई के लिए जमीन से पानी का अत्यधिक दोहन होने के लिए भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। यह समस्या सरकार के सामने भी आ रही है। ऐसे में पानी के किफायती इस्तेमाल की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही उपकरण बनाया है जिससे धान के खेत में पर्याप्त पानी होने की जानकारी किसानों को मिल जाएगी। इससे पानी का सही उपयोग हो सकेगा और किसानों की सिंचाई लागत भी घटेगी। धान की रोपाई का सीजन शुरू हो चुका है। किसानों ने रोपाई के लिए खेत तैयार करने के मकसद से सिंचाई शुरू कर दिए हैं। इस साल बारिश में देरी हो रही है। ऐसे में नहरी पानी उपलब्ध न होने पर जमीन से पानी निकालना किसानों के लिए एकमात्र साधन रह गया है। ऐसे किसानों ने अपने ट्यूबवैलों से सिंचाई शुरू कर दी है। किसान अपने खेतों में तब तक सिंचाई करते रहेंगे जब तक उन्हें खेत में पर्याप्त पानी होने का भरोसा न हो जाए। लेकिन कई बार अनजाने में किसान जरूरत से ज्यादा पानी खेत में भर देते हैं।

स्थिति यह है कि इससे जमीन के पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है। इसके कारण पानी

का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। सिंचाई के लिए कब कितने पानी की जरूरत है, अब यह तकनीकी ढंग से किसानों को पता चल जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी ने एक ऐसा ही मीटर तैयार कर लिया है जो किसानों को बताएगा कि खेत को कब कितना पानी चाहिए। यह मीटर है टैंसो मीटर, जो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी महज 300 रुपये में किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मीटर के उपयोग से किसान 25 से 30 फीसदी तक पानी की बचत कर सकते हैं। यूनीवर्सिटी के मिट्टी व भू विभाग के प्रमुख डॉ. अजमेर सिंह सिद्धू के मुताबिक टेंसो मीटर एक छोटा सा पाइपनुमा मीटर है। इसे 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन में गाड़ दिया जाता है। पाइप के एक सिर पर पोरस कप नाम का उपकरण लगाया जाता है। पाइप पर हरे व पीले रंग की पट्टी हैं। पानी का स्तर जब दोनों पट्टियों के बीच में होता है तो किसान को यह संकेत मिल जाता है कि खेत में पानी की कमी है। उसे बेवजह पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यह उपकरण तभी प्रभावी होगा, जब इसे लगाने से करीब पंद्रह दिन पहले खेत में पानी भरा जाए।

डॉ. सिद्धू के मुताबिक इस यंत्र की बाजार में कीमत करीब 3000 रुपये है जबकि यूनीवर्सिटी इसे सीधे किसानों तक महज 300 रुपये में दे रही है। राज्य में जिस तरह धान से पानी का स्तर नीचे गिर रहा है उसे रोकने के लिए यह उपकरण काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस उपकरण के बार में किसानों को पूरी जानकारी भी दी जा रही है। डॉ. सिद्धू के मुताबिक कई बार ऐसी जमीन रहती है जहां पर पानी का ठहराव कम हो पाता है। ऐसे में किसानों को लगातार पानी देते रहना पड़ेगा। इस यंत्र के बिना किसान कई बार लापरवाही में आवश्यक सिंचाई नहीं करते हैं या फिर कई बार खेतों में पानी इतना ज्यादा दे देते हैं कि वह फसल को फायदा पहुंचाने की बजाए नुकसान पहुंचाने लगता है। यूनीवर्सिटी ने किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए टैंसो मीटर जैसा उपकरण तैयार किया है।

यूनीवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. जी.एस मांगट के मुताबिक धान की फसल के लिए प्रति एकड़ करीब 10 हजार क्यूबिक मीटर पानी का उपयोग हो रहा है। किसान औसतन धान के सीजन में 15 बार सिंचाई करते हैं। किसानों को तकनीकी रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं रहती है कि उन्हें सिंचाई के लिए कब कितना पानी उपयोग करना चाहिए। पानी का ज्यादा उपयोग भी फसल के लिए नुकसानदायक ही रहता है।

इसलिए किसानों को टैंसो मीटर जैसे उपकरण का उपयोग करना चाहिए ताकि गिरते भूजल को बचाया जा सके। पंजाब में हर साल डेढ से दो फीट तक पानी का स्तर नीचे गिर रहा है। जिसका नतीजा यह है कि बड़ी संख्या में किसानों को अपने ट्यूबवैल भी ज्यादा गहरे करवाने पड़ रहे हैं। जिन पर भारी भरकम खर्च आ रहा है।

नीतिगत दरें यथावत रखने से झूमा बाजार

उत्साहित निवेशकों की बदौलत सेंसेक्स 460 अंक उछला

मुंबई । रिजर्व बैंक के नीतिगत दरों को यथावत रखने से उत्साहित निवेशकों की चौतरफा लिवाली की बदौलत आज शेयर बाजार झूम उठा। आरबीआई ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति को नरम रखते हुए नीतिगत दरों को यथावत रखने का निर्णय लिया। इससे हुई चौतरफा लिवाली से बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 460 अंक उछलकर 58926.03 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 126.20 अंक की तेजी के साथ 17590 अंक पर पहुंच गया।

निवेशकों की दिग्गज कंपनियों की तरह छोटी और मझौली कंपनियों में लिवाली की रफ्तार धीमी रही, जिससे बाजार की तेजी नियंत्रित रही। इस दौरान मडकैप 0.30 फीसदी बढ़कर 24,704.65 अंक और स्मॉलकैप 0.04 फीसदी की मामूली बढ़त लेकर 29,246.05 अंक पर रहा। इस दौरान बीएसई में कुल 3448 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 1564 में लिवाली जबकि 1777 में बिकवाली हुई वहीं 107 में कोई बदलाव नहीं हुआ। एनएसई में 38 कंपनियों में तेजी जबकि 12 में गिरावट का रुख रहा। बीएसई में कैपिटल गुड्स समूह की 0.07 फीसदी की गिरावट को छोड़क शेष 18 समूहों में तेजी रही। इस दौरान वित्त 1.06, आईटी 1.02, यूटिलिटीज 1.04, बैंकिंग 1.07, धातु 1.34,टेक 1.01 और पावर समूह के शेयर 1.40 प्रतिशत मजबूत रहे। वैश्विक बाजार की तेजी से भी शेयर बाजार को बल मिला।

सेंसेक्स ने की 345 अंक की तेजी से शुरुआत

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 345 अंक की उछाल लेकर 58,810.53 अंक पर खुला लेकिन बिकवाली होने से थोड़ी देर बाद ही 58,332.28 अंक के निचले स्तर तक लुढ़क गया। इसके बाद शुरू हुई लिवाली की बदौलत यह लगातार बढ़ता हुआ यह कारोबार के अंतिम चरण में 59,060.24 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी भी 90 अंक चढ़कर 17,554.10 अंक पर खुला। सत्र के दौरान यह 17,427.15 अंक के न्यूनतम जबकि 17,639.45 अंक के उच्चतम स्तर पर भी रहा। इस दौरान टाटा स्टील 2.11, इंफोसिस 1.80, एचडीएफसी बैंक 1.77, एचडीएफसी 1.64, कोटक बैंक 1.60, एमएंडएम 1.49, पावरग्रिड 1.31, एनटीपीसी 1.00, एसबीआई 0.99, बजाज फिनसर्व 0.98, आईटीसी 0.91, टेक महिंद्रा 0.88 फीसदी का मुनाफा कमाया।

आरबीआई ने नकदी सुविधा की अवधि बढ़ाई, 30 जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बृहस्पतिवार को आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 50000 करोड़ रुपए की नकदी सुविधा तीन महीने यानी 30 जून, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया। आरबीआई ने पिछले साल मई में तीन साल की अवधि के लिये रेपो दर पर सदा सुलभ नकदी व्यवस्था की घोषणा की थी। इसका मकसद कोविड19 संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बुनियादी ढांचा तथा सेवाओं को मजबूत बनाने के लिये नकदी उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत बैंकों को तेजी से कर्ज देने को लेकर प्रोत्साहित करने के लिये कर्ज को 31 मार्च, 2022 तक प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था। आरबीआई ने बृहस्पतिवार को विकास और नियामकीय नीतियों पर अपने बयान में कहा, योजना को लेकर मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए इसकी अवधि 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 30 जून, 2022 करने का प्रस्ताव है। योजना के अंतर्गत बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि वे कोविड19 कर्ज बही खाता बनाएंगे। अतिरिक्त प्रोत्साहन के तहतए ऐसे बैंक कोविड19 कर्ज खाता के बराबर अपनी अधिशेष नकदी आरबीआई के पास रिवर्स रेपो व्यवस्था के तहत रख सकते हैं। यह दर रेपो दर से 0.25 प्रतिशत कम यानी रिवर्स रेपो से 0.4 प्रतिशत अधिक है। आरबीआई ने कहा कि बैंकों ने चार फरवरी, 2022 तक 9654 करोड़ रुपए का अपना कोष कोविड19 संबंधित आपात स्वास्थ्य सेवाओं के तहत दिया है। केंद्रीय बैंक ने संपर्क गहन क्षेत्रों होटल, पर्यटन आदि के लिये भी हमेशा सुलभ नकदी व्यवस्था 30 जून 2022 तक बढ़ा दी है।

आरबीआई ने ई-रूपी की सीमा बढ़ाई

अब एक लाख रुपए का कर सकते हैं ट्रांजैक्शन

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी की सीमा अब एक लाख रुपए कर दी है। अभी तक यह 10 हजार रुपए थी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक के बाद कहा कि इसे कई सारे उपयोग के लिए भी मंजूरी दी गई है। ई-रूपी के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। इसका उपयोग एक से ज्यादा बार भी किया जा सकता है। ई-रूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का यह पहला कदम था। इसके जरिए आप एसएमएस या फिर एक क्यूआर कोड के जरिए पैसा ले सकते हैं। यह एक तरह से गिफ्ट वाउचर की तरह होता है। इसका उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। सरकार के अनुसार इसके जरिए योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ई-रुपी एक प्रीपेड ई-वाउचर है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने विकसित किया है।

पेट्रोनेट करेगी 40000 करोड़ रुपए का निवेश

पेट्रोरसायन कारोबार क्षेत्र में भी प्रवेश की योजना

नई दिल्ली । दुनिया के सबसे बड़े तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी आयात टर्मिनल का परिचालन करने वाली पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड अगले चार-पांच वर्षों में 40000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी जिसमें विदेशी आपूर्ति स्रोत भी शामिल हैं।

पेट्रोनेट के सीईओ एके सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि कंपनी की पेट्रोरसायन कारोबार क्षेत्र में भी प्रवेश की योजना है। इसके लिए कंपनी एक प्रोपेन डिहाइड्रोजेनरेशन संयंत्र में 12500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी जो आयातित माल को प्रोपिलीन में बदलेगा। सिंह ने कहा कि पेट्रोनेट की ओडिशा के गोपालपुर में 1600 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लोटिंग हवा में तैरती एलएनजी आयात इकाई स्थापित करने की भी योजना है। पिछले साल अमेरिका के लूसियाना में टेल्यूरियन की एलएनजी परियोजना में 2.5 अरब डॉलर निवेश संबंधी गैर बाध्यकारी समझौता करने वाली कंपनी विदेशी परियोजनाओं में निवेश की संभावनाओं पर भी गौर करेगी। सिंह ने कहा, हम विदेशी निवेश के बढ़िया मौकों का मूल्यांकन हमेशा ही करते रहते हैं। अगर ऐसा करना देश के लिए फायदेमंद और बेहतर विकल्प है तो निश्चित रूप से हम ऐसा करेंगे। भारत का घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन ऊर्जा, उर्वरक एवं सीएनजी क्षेत्रों की घरेलू मांग को आधा भी पूरा नहीं कर पाता है। बाकी जरूरत को एलएनजी के रूप में आयात किया जाता है। सिंह ने कहा कि पेट्रोनेट घरेलू एलएनजी आयात क्षमता के विस्तार और पेट्रोरसायन कारोबार पर 17000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

बीएसई को ईजीआर मंच शुरू करने की मंजूरी

नई दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने बीएसई को शेयर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट ईजीआर मंच शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। शेयर बाजार के पास उपलब्ध जारी जानकारी के अनुसार ईजीआर मंच की शुरुआत के लिए अंतिम मंजूरी को लेकर घरेलू बाजार को अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। सेबी ने जनवरी में सोने के शेयर बाजार के संचालन के लिए एक रूपरेखा पेश की थी। इसके तहत ईजीआर के रूप में पीली धातु का कारोबार किया जाएगा। नियामक ने वॉल्ट प्रबंधकों के लिए नियमों को अधिसूचित किया है जिससे गोल्ड बाजार में कारोबार का संचालन किया जाएगा। शेयर बाजार ने कहा, सेबी ने अपने नौ फरवरी, 2022 को एक पत्र के माध्यम से बीएसई लिमिटेड को ईजीआर मंच शुरू करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

रिलायंस ज्वेल्स का वैलेंटाइन्स कलेक्शन फ्लोरियो पेश

मुंबई । भारत में आभूषणों के अग्रणी ब्रांड रिलायंस ज्वेल्स ने अपने प्यार को परवान चढ़ाने की कामना करने वाले सभी लोगों के लिए बेहद खास वैलेंटाइन्स कलेक्शन फ्लोरियो लॉन्च किया है। प्रेमियों के दिलों में बसा प्यार समय के साथ परवान चढ़ता है और उनके रिश्तों में मजबूती आती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिलायंस ज्वेल्स ने वैलेंटाइन्स डे मनाने के लिए कला की बारीकियों एवं आधुनिक डिजाइनों से सुसज्जित इस बेमिसाल डायमंड ज्वैलरी कलेक्शन के लॉन्च के साथ प्यार के मौसम को गले से लगाया है।

इस कलेक्शन में शामिल आभूषणों के डिजाइन पौधों और फूलों से प्रेरित हैं, जो दिन ब दिन बड़े ही मनोहर ढंग से विकसित होते हैं। प्रेम के सच्चे अर्थ को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इस खूबसूरत डायमंड कलेक्शन के प्रत्येक आभूषण को बड़ी सावधानी से तैयार किया गया है, जो आपको हमेशा अपने प्रियजन के साथ रहने और जीवन के सफर में प्यार के सहारे साथ मिलकर आगे बढ़ने की याद दिलाता है। फ्लोरियो सचमुच बेहद खास कलेक्शन है, जो रोज गोल्ड और येलो गोल्ड में आज के जमाने की अंगूठियों तथा पेंडेंट के रूप में बेहद उम्दा डिजाइनों के साथ 12000 रुपए की शुरुआती कीमतों पर उपलब्ध है। यह सही मायने में प्रेम और इसके अटूट बंधनों को दर्शाता है। इस नए कलेक्शन के अलावा रिलायंस ज्वेल्स ने 28 फरवरी तक ड्रीम डायमंड सेल नामक एक खास ऑफर की घोषणा की है, जिसके तहत रिलायंस ज्वेल्स में हीरे के आभूषणों के इनवॉइस मूल्य पर 25 फीसदी तक की छूट शामिल है। ग्राहक सोने के आभूषणों के मेकिंग चार्ज पर भी 25 फीसदी तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह शानदार कलेक्शन रिलायंस ज्वेल्स की वेबसाइट रिलायंसज्वेल्स डॉटकॉम पर इस कलेक्शन की सीमित रेंज उपलब्ध है। सुनील नायक, सीईओ, रिलायंस ज्वेल्स ने कहा, हम अपने नए कलेक्शन फ्लोरियो के जरिए प्रेम के सही अर्थ को अपने मूल्यवान ग्राहकों के साथ अपने दिल में उतारना और साझा करना चाहते हैं। अपने ग्राहकों की खूबसूरती में चार चांद लगाना ही हमारा उद्देश्य रहा है। इस कलेक्शन के आभूषणों के डिजाइन ग्रो इन लव के सिद्धांत से प्रेरित हैं, जिसके साथ हम दुनिया को एक-दूसरे से प्यार करने और एकजुट होकर विकसित होनेए तथा रिश्तों को अटूट बनाने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद करते हैं।

बाजार समीक्षा ब्राजील, अर्जेन्टीना में प्रतिकूल मौसम से सोया उत्पादन प्रभावित

वैश्विक सोयाबीन उत्पादन अनुमान में कमी

इंदौर। अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) की फरवरी में जारी नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील-अर्जेन्टीना में मौसम प्रतिकूल होने से सोयाबीन की फसल प्रभावित हो रही है। इससे सोयाबीन के वैश्विक अनुमान में जनवरी माह की रिपोर्ट की तुलना में कमी दर्शाई गई है।

यूएसडीए की नई रिपोर्ट के अनुसार 2021 -22 के दौरान सोयाबीन का वैश्विक उत्पादन घटकर 36.38 करोड़ टन रह जाएगा, जबकि जनवरी की रिपोर्ट में 37.25 करोड़ टन का अनुमान जताया गया था। इतना ही नहीं पिछले साल 2020-21 की तुलना में भी सोयाबीन का उत्पादन कम रहेगा। गत वर्ष 36.62 करोड़ टन उत्पादन हुआ था। रिपोर्ट में बताया कि विश्व के सबसे बड़े सोया उत्पादक ब्राजील में सोयाबीन का उत्पादन गत माह के 1390 लाख से घटकर 1340 लाख टन रह सकता है, जोकि पिछले साल 1380 लाख टन था। इसी तरह विश्व के

तीसरे बड़े सोया उत्पादक अर्जेन्टीना में उत्पादन पिछले साल के 462 लाख टन से गिरकर 450 लाख टन अनुमानित किया गया है। जनवरी की रिपोर्ट में 465 लाख टन का अनुमान जताया था। इसके अलावा अमेरिका में उत्पादन 1207 लाख टन का अनुमान है, पिछले साल 1147 लाख टन हुआ ता। चीन में सोया उत्पादन गत वर्ष के 196 लाख से गिरकर 164 लाख टन एवं भारत में उत्पादन पिछले साल के 104.5 लाख से बढ़कर 119 लाख टन अनुमानित है।

तिलहन के वैश्विक उत्पादन में भी कमी संभावित

अमेरिकी कृषि विभाग की फरवरी में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर जनवरी के अनुमान की तुलना में प्रमुख तिलहनों के उत्पादन में भी कमी की संभावना जताई गई है। गत जनवरी माह की रिपोर्ट में विश्व का तिलहन उत्पादन 61.91 करोड़ टन अनुमानित किया था, जो फरवरी की रिपोर्ट में घटाकर 61.19 करोड़ टन कर दिया गया है। पिछले साल 2020-21 में 60.36 करोड़ टन तिलहन उत्पादन हुआ था। इसके तहत गत वर्ष की तुलना में सोयाबीन उत्पादन 36.62 करोड़ से घटकर 36.38 करोड़ टन, रेपसीड उत्पादन 7.31 करोड़ से घटकर 7.06 करोड़ टन एवं मूंगफली की उत्पादन 4.95 करोड़ से बढ़कर 5.06 करोड़ टन अनुमानित किया गया है।

तेल प्लांटों की जोरदार मांग से सोयाबीन में तेजी जारी

इंदौर। खाद्य तेलों के बढ़ते दामों के बीच सोयाबीन में तेल प्लांटों की जोरदार मांग से कीमतों में तेजी का रुख देखा जा रहा है। गुरुवार को मलेशिया पामतेल वायदा 1460 डॉलर प्रतिटन था। केएलसीई 63 रिंगिट नीची बंद हुई। शिकागो सोया तेल वायदा रनिंग में 46 सेंट ऊंचा चल रहा था। देश में सोयाबीन आवक 2.65 लाख बोरी हुई। प्लांट सौदों में सोयाबीन धानुका 6800, रूचि 6700, अंबिका 6800, प्रेस्टीज 6750, प्रकाश 6685, महाकाली 6700, रामा 6675, खंडवा 6600, कृति 6650, अवि 6750, एमएस नीमच 6800 रु क्विंटल थे। खाद्य तेल प्रति 10 किलो के सौदो में सोया रिफाइंड 1300-1305, साल्वेंट 1258-1260, मुंबई रिफाइंड 1285, मूंगफली तेल 1320-1340, मुंबई 1330, गुजरात 1290, पाम तेल मुंबई 1235, इंदौर 1320, कपास्या तेल 1255 रु थे।

कपास्या खली में तेजी :मंडियों में कपास आवक घटने लगी है। उत्पादन कम होने की आशंका के बीच गुरुवार को खली बढ़कर प्रति 60 किलो इंदौर 2200, देवास-उज्जैन 2200-2205, खंडवा-बुरहानपुर 2175-2180, रुपए बोरी एवं अकोला 3300 रु प्रति क्विटल थी।

वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा हैं निजी क्रिप्टोकरेंसी

आरबीआई ने किया सावधान

मुंबई। निजी क्रिप्टोकरेंसी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को फिर कहा कि इस तरह की करेंसी व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा हैं। श्री दास ने कहा, हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। इसे आपर निजी क्रिप्टोकरेंसी या जो भी नाम दें, यह हमारी व्यापक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। इस तरह की निजी मुद्राएं वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों से निपटने की केंद्रीय बैंक की क्षमता को कमजोर करती हैं। आरबीआई गवर्नर की ऐसी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में डिजिटल सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर 30 प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की है। निजी क्रिप्टोकरेंसी एक तरह की डिजिटल सम्पत्ति है। निवेश इसकी खरीद बिक्री करते रहते हैं पर भारत में इसे मान्यता नहीं है। श्री दास ने कहा, उन निवेशकों को बताना मेरा कर्तव्य है जो क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं कि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जोखिम पर निवेश कर रहे हैं। उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य किसी ठोस सम्पत्ति पर आधारित नहीं है। भारत में केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी को पेश करने की प्रक्रिया में सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। सीबीडीसी को को पेश करने की समय के बारे में पूछे जाने पर दास ने कहा, मैं समयसीमा नहीं देना चाहूंगा। बजट में एक घोषणा की गई है और हम उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि भारत में डिजिटल मुंद्रा 2022-23 में पेश की जाएगी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि केंद्रीय बैंक पिछले दो साल से सीबीडीसी पर काम कर रहा है और काम जारी है।

मलेशिया से पामतेल निर्यात घटा

इंदौर। फरवरी माह के दौरान विश्व के दूसरे प्रमुख पामतेल उत्पादक देश मलेशिया से निर्यात में कमी का दौर जारी है। 1 से 10 फरवरी के बीच मलेशिया का पाम तेल निर्यात 4.98 प्रतिशत घटकर 3.18 लाख टन रहा, जो कि गत माह 3.34 लाख टन हुआ था।

मलेशिया में गत माह जनवरी में पामतेल उत्पादन 13.54 प्रतिशत घटा था, वहीं मलेशिया से जनवरी में पामतेल का निर्यात भी 18.67 प्रतिशत कम रहा था। जनवरी में पामतेल का स्टॉक 3.85 प्रतिशत घटकर 15.52 लाख टन रहा था। विश्व के सबसे बड़े पामतेल उत्पादक इंडोनेशिया ने निर्यात की पॉलिसी में बदलाव किया है। इससे विश्वबाजार में पामतेल की कीमतों में लगातार बढ़त बनी हुई है। इससे अन्य खाद्य तेलों के वैश्विक दामों में तेजी का दौर देखा जा रहा है। आने वाले समय में कीमतों में और भी तेजी की आशंका है।

एलआईसी के आईपीओ को इरडा की मंजूरी

पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा डिस्काउंट

मुंबई । दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के आईपीओ को बीमा रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडाआई ने मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि कंपनी का वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। एलआईसी इसी हफ्ते मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास आईपीओ के लिए मसौदा जमा करा सकती है। ऐसे में मार्च के मध्य तक इसके इश्यू लाने की उम्मीद है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इसका साइज 60 हजार करोड़ रुपए से 70 हजार करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। सबसे बड़े इश्यू पेटीएम की तुलना में यह करीबन चार गुना ज्यादा होगा। ब्रोकिंग हाउस एंजल वन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एलआईसी का मार्केट कैप 13 से 15 लाख करोड़ रुपए होगा। यानी यह देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद सबसे बड़ी कंपनी होगी। रिलायंस का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपए के करीब है। सरकार एलआईसी आईपीओ में पांच फीसदी हिस्सा बेच सकती है। हालांकि पहले यह 10 फीसदी का अनुमान था। यह बीमा कंपनी आईपीओ में अपने पॉलिसीधारकों और कर्मचारियों के लिए प्राइस बैंड में पांच फीसदी का डिस्काउंट दे सकती है। कंपनी ने पहले ही 10 फीसदी हिस्सा पॉलिसीधारकों के लिए रिजर्व किया है। पिछले हफ्ते विनिवेश विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडा ने कहा था कि इसी हफ्ते में सेबी के पास मसौदा जमा कराया जा सकता है।

कोरोना के चलते जीडीपी में 9.57 लाख करोड़ की भारी गिरावट

वित्तमंत्री सीतारमण ने दी जानकारी

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड19 महामारी की मार से वित्त वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.57 लाख करोड़ रुपए की भारी गिरावट आई। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही।

सीतारमण ने कहा कि अमृतकाल की तरफ बढ़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, आज जनधन योजना के कारण सभी भारतीय समस्त वित्तीय व्यवस्थाओं से जुड़े हैं और इन खातों में 1.57 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। इनमें 55.6 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। उन्होंने कहा कि देश में 2020-21 में 44 यूनिकॉर्न एक अरब डॉलर से अधिक के मूल्यांकन वाली इकाइयां बने जो अमृत काल का ही संकेत है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोजगार की स्थिति में अब सुधार का संकेत दिख रहा है। शहरों में बेरोजगारी अब कोविड पूर्व के स्तर पर आ गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 1.2 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा हुए हैं।

सब्सिडी में कटौती किए जाने से पड़ सकता है खपत पर असर

मुंबई। उपभोक्ता मांग से जुड़ी कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 बड़ा कठिन साबित हो सकता है। सब्सिडी में कटौती, तेल के ऊंचे दाम व ब्याज दरों में बढ़ोतरी सहित कई वजहों से रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुओं (एफएमसीजी) और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों को कठिन दौर से गुजरना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 में खपत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा खाद्य, उर्वरक व ईंधन सब्सिडी में कटौती एवं राजस्व खर्च में कमी हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि यह परिवारों की क्रय शक्ति पर विपरीत असर करेगी। केंद्रीय बजट में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर सब्सिडी में 26.6 प्रतिशत कटौती प्रस्ताव किया है, और इसे वित्त वर्ष 2021-22 के 4.33 लाख करोड़ से घटा कर 3.18 लाख करोड़ रु कर दिया है।

आरबीआई ने वर्तमान परिस्थितियों में उदारवादी रुख जारी रखा

उद्योग जगत ने किया स्वागत

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक आरबीआई के नीतिगत दरों के यथावत बनाए रखने का उद्योग जगत ने स्वागत करते हुए आज कहा कि उसने वर्तमान परिस्थितियों में उदारवादी रुख को जारी रखा है। वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता ने गुरुवार को अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के बीच रिजर्व बैंक ने जीवन और आजीविका को ध्यान में रखते हुए एक उदारवादी रुख जारी रखा है।

आरबीआई ने सामान्य स्थिति में तरलता प्रबंधन के लिए प्रगतिशील रिकवरी की दिशा में कदम उठाए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच बड़ी मैक्रो तस्वीर का सही आकलन किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई के 7.8 प्रतिशत का विकास अनुमान रूढ़िवादी है, यह और अधिक हो सकते हैं। उन्होंने आरबीआई को उसकी तरलता प्रबंधन प्रणाली के लिए बधाई देते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण के दबाव को कम करने के लिए आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि के अलावा विभिन्न साधनों के लिए कोशिश कर रहा है। रियल एस्टेट क्षेत्र को सलाह देने वाली कंपनी नाइट फ्रैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जब अर्थव्यवस्था महामारी की तीसरी लहर के कारण उत्पन्न अस्थिरता से उबर रही है, नीतिगत ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने का आरबीआई का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। अर्थव्यवस्था में अभी भी विकास संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं और आरबीआई का उदार मौद्रिक नीति रुख विकास का समर्थन करेगा। रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी का रुख है और कम ब्याज दरों से इस क्षेत्र के सामर्थ्य में सुधार और विकास की गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

एमएसएमई इकाइयों की डिस्काउंट सुविधा की सीमा तीन करोड़ रुपए

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम एमएसएमई इकाइयों के कारोबार में नकदी का प्रावह बढ़ाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह एनएसीएच में व्यापार के बकायों के डिस्काउंटिंग प्रणाली के जरिए भुगतान के निपटान टीआरईडीएस की सीमा तीन करोड़ रुपए कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा के बाद गुरुवार को मुंबई में कहा कि संबंधित पक्षों ने एमएसएमई क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिए इसका अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एनएसीएच में टीआरईडीएस के लिए निपाटन की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।

अन्य खेल समाचार

IPL 2022 : KL Rahul के बाद अब इस बड़े खिलाड़ी ने पंजाब को छोड़ा

नई दिल्ली. आईपीएल मेगा ऑक्शन से ठीक पहले कुछ टीमों के लिए खबर अच्छी नहीं आ रही हैं. जैसे मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) पोलार्ड की चोट से परेशान हैं और पंजाब को पहले राहुल (KL Rahul) ने छोड़ा, उसके बाद अब बल्लेबाजी कोच ने अपना इस्तीफा दे दिया है, ये अब एक और झटका प्रीति जिंटा को लगा है. झटका इतना बड़ा है कि हो सकता है कि इस बार भी

पंजाब का सरताज बनने का सपना अधूरा ना रह जाए. दरअसल हुआ ये है कि टीम के बल्लेबाज कोच वसीम जाफर ने आईपीएल ऑक्शन से एक दिन पहले टीम को छोड़कर सभी को हैरान कर दिया है.

वसीम ने सोशल मीडिया पर टीम छोड़ने की जानकारी सभी के सामने रखी. अब प्रीति जिंटा के सामने बहुत मुश्किल आ खड़ी हुई है क्योंकि टीम ने बस 2 ही प्लेयर रिटेन किए थे. जिसमें से एक प्लेयर अनकैप्ड है. जिसका ये मतलब हुआ कि टीम पूरी तरह से नई ही बनेगी. साथ में टीम को एक कप्तान भी लेना है. वसीम जाफर के होने से पिछले कुछ सीजनों में टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की है. अब फिर से ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब का आईपीएल सफर अभी ही शुरू हुआ है.

IND vs WI: कोरोना के मात देकर प्लेइंग XI में लौटे? शिखर धवन, जानिए वापसी पर क्या कहा

नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम वनडे इंटरनेशनल मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग XI में तीन बदलाव किया है। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की टीम में वापसी हुई। उनके अलावा कुलदीप यादव और श्रेयस अय्यर की भी टीम में वापसी हुई है। शिखर कोरोना पॉजिटिव होने के कारण पहले और दूसरे वनडे में नहीं खेले थे। लेकिन अब तीसरे वनडे में टीम में उनकी वापसी हुई है। धवन ने वापसी के बाद कहा कि वह अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं।

धवन ने मैच से पूर्व कहा, 'मैं अच्छी लय में हूं। मुझे खुशी है कि मैंने पांच अर्द्धशतक (पिछली नौ पारियों में) लगाए हैं। कई बार शतक बनाने से भी चूका हूं और मैं उन सब चीजों पर विचार करता हूं। मैं जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा हूं उससे मैं बहुत खुश हूं। मैं हमेशा रनों के लिए भूखा रहता हूं लेकिन साथ ही मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं सिर्फ शतकों पर नहीं बल्कि समय की मांग के हिसाब से अपने खेल पर ध्यान दूं।'

उन्होंने कहा, ' यह अच्छा है कि टीम में कई सारे ओपनर है। लेकिन मेरा पूरा ध्यान अपने खेल पर और टीम के लिए अपना योगदान देने पर है। जब मैं टीम के लिए अपना योगदान देता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा किसी से मुकाबला नहीं है।

पंजाब किंग्स को लगा एक और झटका, IPL 2022 मेगा ऑक्शन में शामिल नहीं हो पाएंगी प्रीति जिंटा

नई दिल्ली. आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 के शुरू होने से पहले ही पंजाब किंग्स (Punjab Kings) को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बैटिंग कोच वसीम जाफर के अपने से इस्तीफा देने के बाद टीम की सह-मालकिन प्रीति जिंटा को लेकर एक निराशाजनक खबर सामने आ रही है। प्रीति जिंटा इस बार निजी कारणों से आईपीएल नीलामी में शामिल नहीं हो पाएंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि वह हाल में मां बनी और इसलिए वह अपने बच्चों की वजह से इस बार नीलामी के लिए भारत नहीं आ पाएंगी। नीलामी 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में शुरू होने वाली है।पंजाब किंग्स की सह-मालकिन प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर लिखा, 'मैं आईपीएल नीलामी में इस साल शामिल नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर भारत नहीं आ सकती। पिछले कुछ दिन मैं और हमारी टीम साथ में नीलामी और क्रिकेट की सभी चीजों पर चर्चा में व्यस्त रहे हैं। मैं अपने फैंस तक यह जानकारी देना चाहती थी और उनसे पूछना था कि क्या उनके पास कोई खिलाड़ी सुझाव या हमारी नई टीम के लिए कोई सिफारिश है। मुझे यह जानकर अच्छा लगेगा कि आप इस साल लाल जर्सी में किसे देखना चाहते हैं। इससे पहले, टीम के बल्लेबाजी कोच

वसीम जाफर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह 2019 में बतौर बल्लेबाजी कोच पंजाब किंग्स से जुड़े थे। पंजाब किंग्स ने नीलामी से पहले मयंक अग्रवाल को 12 करोड़ रुपये में और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। पंजाब के पास इस समय पर्स में 72 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 43 साल के जाफर ने रनबीर कपूर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल फिल्म के गाने अच्छा चलता , दुआओं में याद रखना की तस्वीर पोस्ट करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी।

IND vs WI: ऋतुराज गायकवाड़ ने दी कोरोना को मात, तीसरे वनडे खेलना फिर भी मुश्किल, जानें वजह

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से महज चार दिन पहले कोरोनावायरस की चपेट में आए सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ अब इस माहामारी को मात देते हुए आइसोलेशन से बाहर आ गए हैं। मगर ऋतुराज का वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी वनडे में खेलना अभी भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। रोहित शर्मा दूसरे वनडे में मिली जीत के बाद हिंट दे चुके हैं कि शिखर धवन आखिरी मैच में उनके साथ ओपनिंग करेंगे।ऋतुराज पिछले कुछ समय से मैदान के बाहर बैठकर ही मैच देख रहे हैं।न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में वह बेंच पर रहे थे, वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी गायकवाड़ को खेलने का मौका भी नहीं मिला था। उम्मीद जताई जा रही थी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में उन्हें प्लेइंग

इलेवन में मौका मिल सकता है। मगर महामारी की चपेट में आने की वजह से यह उम्मीद भी टूटती हुई दिखाई दे रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद भारत को तीन मैच की टी20 सीरीज भी खेलनी है, मगर टी20 में ऋतुराज गायकवाड़ शामिल नहीं है, ऐसे में वह रणजी ट्रॉफी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं।बता दें, 2 फरवरी को भारतीय टीम में हुई कोरोनावायरस की एंट्री में तीन खिलाड़ी संक्रमित पाए गए थे।

IPL 2022 नीलामी में इन 3 ऑलराउंडरों की होगी भारी डिमांड, सभी 10 टीमों की नजरें इन्हीं पर

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 नीलामी (IPL 2022 Mega Auction) को शुरू होने में अब केवल एक ही दिन का समय बचा है। बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को होने वाली नीलामी में लीग की सभी 10 टीमों की नजरें बड़ बड़े खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने की होगी। साथ ही फ्रेंचाइजियों की नजरें ऑलराउंडर खिलाड़ियों पर भी होगी। टी20 क्रिकेट में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की काफी अधिक डिमांड होती है। ये खिलाड़ी अच्छी गेंदबाजी के साथ-साथ तेजी से रन बनाने में भी माहिर होते हैं। आईपीएल 2022 नीलामी में इस बार कई ऑलराउंडर बिकने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ ऐसे भी ऑलराउंडर है, जिनपर फ्रेंचाइजी बड़ा दांव लगाने से पीछे नहीं हटेगी। आइये आपको उन 3 शानदार ऑलराउंडरों के बारे में बताते हैं, जिन पर नीलामी के दौरान सभी टीमों की नजर रहने वाली है।

जेसन होल्डर

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर इस समय भारत में ही लिमिटेड ओवरों की सीरीज खेल रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपने घर में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 गेंदों पर लगातार 4 विकेट चटकाए थे। होल्डर तेज गेंदबाजी के साथ-साथ मध्यक्रम या निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। उन्होंने आईपीएल के 26 मैचों में 22.46 की औसत से 35 विकेट लिए हैं और साथ ही 121.15 की स्ट्राइक रेट से 189 रन भी बनाए हैं। होल्डर पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद टीम में शामिल थे।

मिचेल मार्श

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श टी20 वर्ल्ड कप में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर मैन ऑफ द मैच रहे थे। उन्होंने बल्लेबाजी में 77 रनों की नाबाद पारी खेली थी। आईपीएल 2020 में वह? सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा थे, लेकिन चोटिल हो जाने के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। वहीं, 2021 में वह? नहीं खेले थे। मिचेल मार्श ने आईपीएल में 21 मैचों में 21 की औसत से 20 विकेट चटकाए हैं और साथ ही 15 पारियों में 114.21 की स्ट्राइक रेट से 225 रन भी बनाए हैं। मार्श बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी योगदान देने की काबिलियत रखते हैं और इसी वजह से नीलामी में इनकी काफी मांग हो सकती है।

शाहरुख खान

भारतीयों में तमिलनाडु के ऑलराउंडर शाहरुख खान अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।

IPL Mega Auction 2022 : ऑक्शन शुरू होने से पहले ही मुंबई को करारा झटका!

नई दिल्ली. एक दिन बाद यानी 12 फरवरी से आईपीएल का मेगा ऑक्शन शुरू होना है लेकिन ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है. दरअसल आप जानते ही हैं कि पुरानी आठ टीमों ने अपने रिटेन किए प्लेयर्स की लिस्ट BCCI को बहुत समय पहले ही थी. अगर मुंबई की बात करें तो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ बुमराह, सूर्य कुमार यादव और पोलार्ड को टीम ने अपने साथ जोड़ कर रखा था. पर इस रिटेन लिस्ट में एक ऐसा प्लेयर है जो मुंबई को करारा झटका दे सकता है.

दरअसल हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर पोलार्ड की. पोलार्ड को मुंबई ने 6 करोड़ में रिटेन किया हुआ है. साथ ही कई बड़े नामों को मुंबई की टीम ने पोलार्ड के लिए छोड़ दिया था, मसलन ईशान किशन, डी कॉक, कुणाल पांड्या। पर अब खबर ये है कि पोलार्ड की फिटनेस उनका साथ नहीं दे रही है.पोलार्ड ने भारत के साथ हुए दूसरे वनडे को अपनी चोट की वजह से मिस किया था. और रिपोर्ट्स हैं कि

चोट गंभीर भी हो सकती है. ऐसे में मुंबई का रिटेन वाला प्लान यहां बिगड़ सकता है. क्योंकि पिछले कई साल की बात करें तो देखा गया है कि पोलार्ड जब भी चोटिल होते हैं तो वापसी काफी समय बाद होती है. ऐसे में अगर पोलार्ड की फिटनेस उनका साथ नहीं देती है तो रोहित शर्मा को अपना प्लान बदलना ही होगा.

ये 3 युवा भारतीय खिलाड़ी आने वाले समय में मचाएंगे धमाल, रिकी पोंटिंग ने बताए नाम

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने हाल ही में तीन ऐसे युवा भारतीय खिलाड़ियों के नाम बताएं है जो आने वाले समय में क्रिकेट की दुनिया में धमाल मचा सकते हैं। पोंटिंग आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं और उन्हें आईपीएल के दौरान कई युवा प्रतिभाओं ने प्रभावित किया है। पोंटिंग ने आईसीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित एक इंटरव्यू में इन तीन नाम का खुलासा किया है।

रिकी पोंटिंग ने इन तीन खिलाड़ियों में दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और तेज गेंदबाज आवेश खान के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ को चुना है।पोंटिंग ने कहा "इनमें हमारे रिटेन किए गए खिलाड़ियों में से एक पृथ्वी शॉ हैं,

जिन्हें हमने पिछले साल आईपीएल सीजन के दौरान कुछ शानदार प्रदर्शन करते देखा था। हर कोई उसके बारे में पिछले कुछ वर्षों से जानता है। मुझे अब भी लगता है कि वह एक व्यक्ति के रूप में अपने बारे में बहुत कुछ सीख रहा है और एक खिलाड़ी के रूप में अपने बारे में बहुत कुछ सीख रहा है।"शॉ के बारे में ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान ने आगे कहा "वह ऐसा खिलाड़ी है कि जब वह अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहा होता है तो ज्यादा बल्लेबाजी नहीं करना चाहता। जब वह अच्छी बल्लेबाजी कर रहा होता है तो वह हर समय बल्लेबाजी करना चाहता है। यह उस तरह के अनाज के खिलाफ गया जो मैंने महसूस किया और एक खिलाड़ी के रूप में खुद को जानता था। लेकिन उसमें से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए, हम उसे जाने देंगे और खुद को व्यवस्थित और व्यवस्थित कर लेंगे।"

उन्होंने आगे कहा "मुझे जो दूसरा खिलाड़ी लगता है वो चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ हैं जो काफी लाजवाब हैं। मैंने उन्हें टी20 में ही खेलते हुए देखा है। वह आईपीएल विजेता टीम का हिस्सा है जिसे सीजन की शुरुआत से ही खेलने का मौका मिला। सब जानते हैं कि वह लाजवाब खिलाड़ी है और टेकनिकल रूप से कितने पूर्ण हैं। आईपीएल के खत्म होते-होते उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक चीजें की। वह ऐसा खिलाड़ी है जो आने वाले समय में भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलेगा।"

तीसरे खिलाड़ी के बारे में बात करते हुए पोंटिंग ने कहा "हमारे पास दिल्ली कैपिटल्स में आवेश खान हैं, जिनका पिछला सीजन शानदार रहा था। उन्हें भारतीय टीम में भी शामिल किया गया है।"

आईपीएल मेगा नीलामी में मिशेल स्टार्क के शामिल नहीं होने की उम्मीद

सिडनी. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने कहा है कि उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की 12-13 फरवरी को बेंगलुरू में होने वाली नीलामी के लिए नामांकन नहीं किया है।

कुल 47 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने आईपीएल नीलामी के लिए नामांकन किया है, लेकिन हाल ही में समाप्त हुई एशेज श्रृंखला के दौरान शानदार फॉर्म में चल रहे स्टार्क ने मेगा नीलामी से बाहर होने का विकल्प चुना है।स्टार्क शुक्रवार को बाद में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के टी20आई ओपनर में शामिल होंगे । यह अनुमान है कि वर्षो से आईपीएल की नीलामी में भाग नहीं लेने के उनके फैसले से उन्हें लगभग 10 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। स्टार्क आखिरी बार आईपीएल 2015 में खेले थे।बाएं हाथ के गेंदबाज आईपीएल में सबसे अधिक मांग वाले क्रिकेटरों में से एक हैं और पिछली दो नीलामियों में स्टार्क की टीम के साथी, टेस्ट कप्तान पैट कमिंस और झे रिचर्डसन ने 5.6 मिलियन डॉलर की फीस ली थी।

स्टार्क ने कहा, एक समय होगा जब मैं आईपीएल में वापस जाना पसंद करूंगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जितना हो सके उतना खेलना चाहता हूं, यह फैसला मैंने कुछ समय के लिए किया है।

स्टार्क , जिन्हें 2014 की नीलामी में आईपीएल की ओर

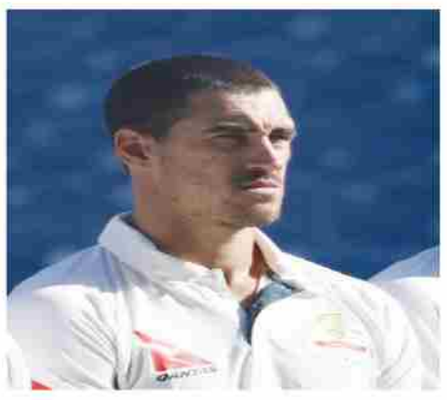

से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु द्वारा 8,88,000 डॉलर में चुना गया था, चोट के कारण 2016 के सीजन में वे नहीं खेले। इसके बाद उन्होंने 2017 की नीलामी में प्रवेश नहीं किया।उन्हें 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1.8 मिलियन डॉलर में खरीदा था। फिर से चोटिल होने के बाद उन्होंने उस वर्ष के विश्व कप से पहले 2019 के टूर्नामेंट को छोड़ दिया। 2020 में, तेज गेंदबाज ने कई फ्रेंचाइजी द्वारा रुचि दिखाने के बावजूद आईपीएल में भाग नहीं लेने का फैसला किया। पैट कमिंस तब 3.17 मिलियन डॉलर की राशि के साथ खरीदे गए थे।2022 की आईपीएल नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल :200 लाख रुपए का आधार मूल्य (लगभग 3,77,000 डॉलर) :पैट कमिंस, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मिच मार्श, मैथ्यू वेड, जोश हेजलवुड, एडम जम्पा, नाथन कूल्टर-नाइल, एश्टन एगर।बेस प्राइस 150 लाख रुपए (लगभग 2,83,000 डॉलर)एरोन फिंच, क्रिस लिन, उस्मान ख्वाजा, केन रिचर्डसन।बेस प्राइस 100 लाख रुपए (लगभग 1,89,000 डॉलर)मार्नस लाबुस्चागने, डैनियल सैम्स, एंड्रयू टाय, मोइसेस हेनरिक्स, रिले मेरेडिथ, जेम्स फॉल्कनर, डीआर्सी शॉर्ट, जोश फिलिप।बेस प्राइस 75 लाख रुपए (लगभग 1,42,000)

नाथन एलिस, जेसन बेहरेनडॉर्फ , सीन एबॉट, बिली स्टेनलेक, बेन कटिंग।बेस प्राइस 50 लाख रुपए (लगभग 94,000 डॉलर)बेन मैकडरमोट, कुर्टिस पैटरसन, वेस एगर, जैक वाइल्डरमुथ, जोएल पेरिस, हिल्टन कार्टराइट।बेस प्राइस 40 लाख रुपए (लगभग 75,000 डॉलर)

टिम डेविड, क्रिस ग्रीन।बेस प्राइस 30 लाख रुपए (लगभग 57,000 डॉलर)

बेन द्वारशुइस, मैट केली।

बेस प्राइस 20 लाख रुपए (लगभग 38,000 डॉलर)

हेडन केर, तनवीर संघा, एलेक्स रॉस, जेक वेदरल्ड, नाथन मैकएंड्रयू, टॉम रोजर्स, लियाम गुथरी, लियाम हैचर, जेसन संघ, मैट शॉर्ट, एडन काहिल।

आईएसएल 2021-22 : जमशेदपुर केरल पर जीत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा

➤आईएसएल 2021-22 : जमशेदपुर केरल पर जीत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा

बम्बोलिम (गोवा). जमशेदपुर एफसी गुरुवार को यहां एथलेटिक स्टेडियम में खेले गए हाई-वोल्टेज इंडियन सुपर लीग मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स को 3-0 से हराकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया।

ग्रेग स्टीवर्ट (45वें, 48वें) ने हाफटाइम के दोनों ओर मौके से दो गोल किए, इससे पहले डेनियल चीमा चुकु (53वें) ने अपने रैंक में शामिल होने के बाद से लगातार तीसरे गेम के लिए नेट पर वापसी की। जमशेदपुर के अब 14 मैचों में 25 अंक हो गए हैं, जो तालिका में शीर्ष पर रहने वाली हैदराबाद एफसी से कम है, जिसके 15 मैचों में 26 अंक हैं। केरल 14 मैचों में 23 अंकों के साथ हार के बाद पांचवें स्थान पर खिसक गया।जमशेदपुर ने शुरुआती आदान-प्रदान में अधिक गेंद देखी, क्योंकि दोनों टीमों ने सावधानी से शुरुआत की, यह पता लगाने की कोशिश की कि दूसरा क्या कर रहा है। कूलिंग ब्रेक से पहले कोई वास्तविक मौका नहीं था जिसके बाद केरल ने एक साथ काम किया और गेंद को अधिक रखा और अब्दुल सहल, एड्रियन

लूना और अल्वारो वाजक्वेज की पसंद के साथ खेल में अधिक प्रभाव था।दूसरे हाफ में जमशेदपुर ने पांच मिनट के अंतराल में खेल को खत्म करने के लिए दो गोल किए। सबसे पहले, बोरिस सिंह को बॉक्स के अंदर मार्को लेस्कोविक द्वारा मेन ऑफ स्टील को एक और पेनल्टी सौंपने के लिए क्लिप किया गया था। स्टीवर्ट ने कदम बढ़ाया और मौके से अपनी संख्या को दोगुना कर दिया, कीपर को फिर से गलत तरीके से भेज दिया।हाफ वॉली पर घर में आग लगाने के लिए बोरिस द्वारा लो क्रॉस में भेजे जाने के बाद चीमा ने खेल को केरल से दूर ले लिया। गिल को अपनी लाइन से बाहर देखकर ऋत्विक दास ने दूर से अपनी किस्मत आजमाई लेकिन गेंद गोल की छत पर चली गई।डिस्क्लेमर: यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

राज्यसभा में बजट सत्र का प्रथम चरण संपन्न, सदन की कार्यवाही 14 मार्च तक स्थगित

नई दिल्ली, 11 फरवरी (एजेन्सी)। राज्यसभा की कार्यवाही आम बजट 2022-23 पर हुई चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जवाब दिए जाने के बाद शुक्रवार को 14 मार्च सुबह दस बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी और इसी के साथ उच्च सदन में बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हुआ।

कार्यवाही स्थगित करने से पहले उपसभापति हरिवंश ने बजट सत्र के पहले चरण में उच्च सदन में जिस तरह से कामकाज हुआ, उसे लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू और अपनी तरफ से प्रसन्नता जतायी।

उन्होंने कहा कि इस दौरान एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब सदन को (व्यवधान और शोरगुल की) विवशता के कारण स्थगित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के पहले चरण में उच्च सदन में निर्धारित समय से आधे घंटे अधिक कामकाज हुआ।

हरिवंश ने कहा कि इसका श्रेय सदन के प्रत्येक सदस्य को जाता है। उन्होंने कहा कि इसके कारण सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले सके। उन्होंने कि बजट सत्र के पहले चरण में सदन में 51 तारांकित प्रश्न पूछे गए वहीं लोक महत्व के 50 मुद्दे एवं शून्यकाल में विभिन्न मुद्दे उठाये गये।

उपसभापति ने सदन के सभी वर्गों को सकारात्मक भावना के साथ कामकाज करने की बधाई दी और उम्मीद जतायी कि आगे भी सदन इसी भावना के साथ काम करता रहेगा।

उल्लेखनीय है कि संसद के बजट सत्र की शुरूआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी। उसी दिन दोनों सदन में आर्थिक समीक्षा पेश की गयी थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को संसद के दोनों सदनों में आम बजट एवं संबंधित दस्तावेज रखे थे। दो फरवरी से दोनों सदनों में पहले राष्ट्रपति अभिभाषण और फिर आम बजट पर चर्चा की गयी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया था।

सदन में चार फरवरी को शुक्रवार होने के कारण गैर सरकारी कामकाज हुआ था किंतु सभी दलों के बीच बनी सहमति के कारण आज सदन में गैर सरकारी कामकाज नहीं हुआ।

बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से आठ अप्रैल तक चलने का कार्यक्रम है।

विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी : पीएम मोदी

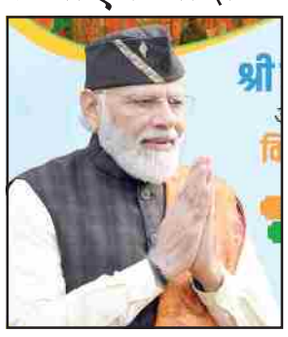

अल्मोड़ा, 11 फरवरी (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को यहां आयोजित एक रैली में कहा कि उत्तराखंड का विकास भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की डबल इंजन की सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास भाजपा की प्राथमिकता है और लोगों को पर्वतमाला एवं वाइब्रेंट ग्राम परियोजनाओं से लाभ होगा। मोदी ने घोषणा की कि जमरानी बांध परियोजना पर काम जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मानसखंड पर्यटन सर्किट को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा।

रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि अत्यधिक संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि उत्तराखंड ने डबल इंजन की सरकार के लिए एक बार फिर मतदान करने का मन बना लिया है।

राज्य में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही चरण में, 14 फरवरी को मतदान होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 2 हफ्ते के अंदर पेश होने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 11 फरवरी (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बैंकों द्वारा दायर अवमानना मामले में सजा सुनाने से पहले पेश होने का अंतिम मौका दिया, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया है।

जस्टिस यू. यू. ललित और एस. रवींद्र भट की बेंच ने कहा कि अदालत ने माल्या को अवमानना का दोषी पाया है और उन्हें सजा दी जानी चाहिए। सामान्य तर्क के आधार पर अवमाननाकर्ताको सुना जाना चाहिए, लेकिन वह अब तक अदालत में पेश नहीं हुए हैं।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार-बार समन किए जाने के बावजूद विजय माल्या अब तक पेश नहीं हुए। इसके चलते कोर्ट ने उन्हें 2017 में अवमानना के मामले में भी दोषी ठहराया था। हालांकि, कोर्ट के लंबे इंतजार के बावजूद माल्या इस मामले में एक भी बार पेश नहीं हुए हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता, जो न्याय मित्र (एमिक्स क्यूरी) हैं, ने प्रस्तुत किया कि मामले को थोड़े समय के लिए इस अभिव्यक्ति के साथ स्थगित किया जा सकता है कि यह अंतिम अवसर हो सकता है।

न्यायमूर्ति भट ने कहा कि माल्या ने अब तक सुनवाई से परहेज किया है और अगली सुनवाई में भी यही होगा और फिर अदालत को अनुपस्थिति में सजा सुनानी होगी।

जस्टिस ललित ने कहा कि उन्हें कई मौके दिए जा चुके हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि यह भारत सरकार का स्टैंड नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ गोपनीय कार्यवाही ब्रिटेन (यूके) में लंबित है, बल्कि यह यूके सरकार का स्टैंड है, जो उनके प्रत्यर्पण में देरी कर रहा है। पीठ मेहता की दलीलों को रिकॉर्ड में लेने के लिए तैयार हो गई।

पीठ ने कहा कि न्याय मित्र का कहना है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है और अवमानना करने वाले को पर्याप्त अवसर दिया गया है। इसलिए अब मामले को थोड़े समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, और अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए।

दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की। इसने यह भी स्पष्ट किया कि अगर माल्या सुनवाई में मौजूद नहीं होते हैं तो मामले को निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा।

14 जुलाई, 2017 को दिए गए एक फैसले के अनुसार, माल्या को बार-बार निर्देशों के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी पाया गया था। इसके अतिरिक्त, उन पर अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करने और वसूली (रिकवरी) की कार्यवाही के उद्देश्य को विफल करने के लिए गुप्त रूप से संपत्ति के निपटान का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया है।

6 अक्टूबर, 2020 को, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूके के गृह कार्यालय ने सूचित किया है कि एक और कानूनी मुद्दा है, जिसे माल्या के प्रत्यर्पण से पहले हल करने की आवश्यकता है। ब्रिटेन के कानून के तहत इसी कानूनी पेंच के कारण उनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया में देरी हो रही है।

हलफनामे में कहा गया था कि प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील हारने के बाद, भारत के लिए माल्या का आत्मसमर्पण, सिद्धांत रूप में, 28 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए था। हालांकि, यूके के गृह कार्यालय ने भारत को आगे के कानूनी मुद्दे के बारे में सूचित किया।

पिछले साल 2 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने केंद्र से भगोड़े व्यवसायी के प्रत्यर्पण पर छह सप्ताह के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। 30 नवंबर को अदालत ने कहा कि वह अदालत की अवमानना में उसे सजा देने पर सुनवाई शुरू करेगी, जिसमें उन्हें जुलाई 2017 में दोषी ठहराया गया था।

भाजपा में स्वाभिमानी सवर्णों को कोई स्थान नहीं : सुरेंद्र सिंह

बलिया, 11 फरवरी (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट कटने के बाद भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले विधायक सुरेंद्र सिंह ने विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर लिया है। शुक्रवार को सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा में स्वाभिमानी सवर्णों के लिए कोई स्थान नहीं है।

शुक्रवार को विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधायक सुरेंद्र सिंह ने जिले के बैरिया विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में चाटूकारिता की संस्कृति का बोलबाला हो गया है।

उन्होंने कहा कि अमित शाह और संदीप बंसल का पैर छूने वाले को टिकट दिया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि यदि वह विधायक निर्वाचित हुए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन करेंगे। इसके जवाब में सिंह ने कहा कि अब उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बजाय विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का सम्मान मायने रखता है।

उधर, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को बलिया सदर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजभर का सम्मान भाजपा की बदौलत ही बढ़ा है और भाजपा से गठबंधन के बाद वह विधायक बने हैं।

उन्नाव में लापता दलित लड़की का शव पूर्व मंत्री के आश्रम के पास मिला, मायावती ने सपा को घेरा

उन्नाव, 11 फरवरी (एजेन्सी)। उन्नाव में एक 22 वर्षीय दलित महिला के लापता होने के दो महीने बाद, पुलिस ने राज्य के एक पूर्व मंत्री के बेटे के आश्रम के पास से उसका क्षत-विक्षत शव बरामद किया है।

जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र से पिछले दो माह से लापता एक युवती का शव समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह द्वारा बनवाए गए आश्रम के पास खाली जमीन से बरामद किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

मामले का मुख्य आरोपी रजोल सिंह सपा नेता फतेह बहादुर का बेटा है। अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शशि शेखर सिंह ने बताया कि युवती के लापता होने के बाद चार फरवरी को पुलिस ने एक आरोपी रजोल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। बाद में विशेष अभियान समूह (एसओजी) की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से मिली जानकारी के आधार पर और आरोपी के एक साथी की निशानदेही पर आश्रम के पास की जमीन से बृहस्पतिवार को युवती का शव बरामद किया।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को सपा पर निशाना साधते हुए मांग की है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे।

अपर पुलिस अधीक्षक सिंह ने बताया मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। जांच की जा रही है और जल्द इसमें शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गौरतलब है कि कुछ दिनों से लापता युवती की मां ने लखनऊ में सपा नेता की कार के आगे आत्मदाह का प्रयास किया था। बृहस्पतिवार को शव मिलने के बाद युवती की मां ने कहा कि वह पहले दिन से ही कह रही थीं कि उनकी बेटी का पूर्व मंत्री के बेटे रजोल सिंह ने अपहरण किया। महिला ने इस बीच स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया और किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए उनसे लगातार आरोपी रजोल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए युवती की मां ने 24 जनवरी को लखनऊ में आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने रजोल सिंह को गिरफ्तार किया था।

कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी निवासी एक दलित महिला की बेटी आठ दिसंबर 2021 से गायब थी। युवती की मां ने नौ दिसंबर को पूर्व मंत्री के बेटे रजोल सिंह के खिलाफ बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था।

बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट कर सपा पर निशाना साधते हुए कहा, उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अत्यंत दुःखद एवं गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही युवती के अपहरण और हत्या की आशंका जता रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे।'

आम बजट में आजाद भारत के 100 साल को लेकर दूरदृष्टि : सीतारमण

राजेश अलख

नई दिल्ली, 11 फरवरी । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि आम बजट 2022-23 का महत्वपूर्ण उद्देश्य निरंतरता को बनाए रखना है और इससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी।

राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने को लेकर एक दूरदृष्टि है और इसके मद्देनजर सरकार का ध्यान विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा, भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ में कहां होगा, यदि इसके बारे में एक दूरदृष्टि नहीं होगी तो हमें उसका खामियाजा ठीक उसी तरह भुगतना होगा, जैसा हमने पहले 70 सालों में उठाया। और इनमें से 65 साल कांग्रेस ने शासन किया। उस कांग्रेस ने, जिसके पास कोई दूरदृष्टि नहीं थी सिवाय एक परिवार को फायदा पहुंचाने के। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.57 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ जबकि 2008-09 की वैश्विक मंदी में 2.12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2008-09 में जब वित्तीय संकट कम गंभीर था, मुद्रास्फीति की दर 9.1 प्रतिशत थी जबकि महामारी का अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव पड़ा लेकिन उस दौरान यह दर 6.2 प्रतिशत रही। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह भारतीय कृषि को बेहतर और आधुनिक बनाने में कारगर साबित होगा।

वित्त मंत्री ने राज्यसभा में आम बजट पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट निरंतरता, कराधान के अनुमान और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए है। उन्होंने कहा कि बजट का मकसद अर्थव्यवस्था को स्थिर और स्थायी प्रोत्साहन देना है।

उन्होंने 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान संप्रग सरकार के प्रदर्शन की तुलना करते हुए कहा कि उस वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति की दर 9.1 प्रतिशत थी, जबकि कोविड महामारी के दौरान यह 6.2 प्रतिशत रही जबकि अर्थव्यवस्था पर इसका काफी अधिक प्रभाव पड़ा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा संकुचन हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को महामारी के कारण 9.57 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ जबकि 2008-09 में वैश्विक मंदी के समय 2.12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

उन्होंने कहा कि राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय कई गुना अधिक लाभ देता है और इसलिए सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने पर जोर दिया है।

सीतारमण ने कहा कि सरकार स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रही है जिसके फलस्वरूप महामारी के दौरान कई यूनिकॉर्न की स्थापना हुयी।

हिजाब मामले पर दखल से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- हाईकोर्ट को देखने दीजिए, हम सही वक्त पर सुनवाई करेंगे

नई दिल्ली, 11 फरवरी (एजेन्सी)। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होने दीजिए, वह सही वक्त पर सुनवाई करेगा।

ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा और कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उचित समय पर विचार करेगा, जिसमें विद्यार्थियों से शैक्षणिक संस्थानों में किसी प्रकार के धार्मिक कपड़े नहीं पहनने के लिए कहा गया है। न्यायालय ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं फैलने पर भी जोर दिया।

प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ को छात्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश ने संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया है।

उन्होंने याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध भी किया।

याचिका 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध अस्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने इस मामले में जारी सुनवाई का हवाला दिया और कहा कि हम प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और मामले पर उचित समय पर सुनवाई की जाएगी।

कामत ने इसके बाद कहा, मैं उच्च न्यायालय द्वारा कल हिजाब के मुद्दे पर दिए अंतरिम आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर रहा हूं। मैं कहूंगा कि उच्च न्यायालय का यह कहना अजीब है कि किसी भी छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने पर अपनी धार्मिक पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए। न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी इसके दूरगामी प्रभाव हैं।

उन्होंने सिखों के पगड़ी पहने का जिक्र किया और कहा कि उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में सभी छात्रों को निर्देश दिया है कि वे अपनी धार्मिक पहचान बताए बिना शिक्षण संस्थानों में जाएं।

कामत ने कहा, हमारा सम्मानजनक निवेदन यह है कि जहां तक हमारे मुवक्किल की बात है, यह अनुच्छेद 25 (धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता) के पूर्ण निलंबन के बराबर है। इसलिए कृपया अंतरिम व्यवस्था के तौर पर इस पर सुनवाई करें।

कर्नाटक सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश अभी तक नहीं आया है और इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए।

पीठ ने कहा, उच्च न्यायालय मामले पर त्वरित सुनवाई कर रहा है। हमें नहीं पता कि क्या आदेश सुनाया जाएगा...इसलिए इंतजार करें। हम देखते हैं कि क्या आदेश आता है।

याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। उन्होंने कहा, यह अदालत जो भी अंतरिम व्यवस्था तय करेगी वह हम सभी को स्वीकार्य होगी।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इन चीजों को व्यापक स्तर पर ना फैलाएं। हम बस यही कहना चाहते हैं, कामत जी हम भी सब देख रहे हैं। हमें भी पता है कि राज्य में क्या हो रहा है और सुनवाई में क्या कहा जा रहा है...और आप भी इस बारे में विचार करें कि क्या इन चीजों को दिल्ली के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना सही है।

उच्च न्यायालय के आदेश में कानूनी सवाल उठने की दलील पर पीठ ने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ होगा, तो उस पर गौर किया जाएगा।

पीठ ने कहा, यकीनन हम इस पर गौर करेंगे। निश्चित रूप से, अगर कुछ गलत होता है तो हम उसे सही करेंगे। हमें सभी के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करनी है...इस समय उसके गुण-दोष पर बात ना करें। देखते हैं क्या होता है। हम उचित समय पर इस पर हस्तक्षेप करेंगे। हम उचित समय पर मामले पर सुनवाई करेंगे।

हिजाब के मुद्दे पर सुनवाई कर रही कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को मामले का निपटारा होने तक छात्रों से शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में धार्मिक कपड़े पहनने पर जोर नहीं देने के लिए कहा था। इसके निर्देश के खिलाफ ही उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

एक छात्र द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय के निर्देश के साथ ही तीन न्यायधीशों की पीठ के समक्ष चल रही सुनवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देकर उनके मौलिक अधिकार कम करने की कोशिश की।

गौरतलब है कि उडुपी के एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ छात्राओं के निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए हिजाब पहनकर कक्षाओं में आने पर, उन्हें परिसर से बाहर जाने को कहा गया, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया और राज्य भर में प्रदर्शन हुए। इसके जवाब में हिंदू छात्र भी भगवा शॉल ओढ़कर विरोध करने लगे।

KENDRIYA VIDYALAYA, GANGTOK

WALK-IN-INTERVIEW

Walk-in-interview of Part time Contractual teachers for various posts in Kendriya Vidyalaya Gangtok is going to be conducted on 28th Feb 2022 (Monday) from 08:00 AM for the session 2022-23. For detailed information, visit our website :

https://gangtok.kvs.ac.in

Principal

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रकः नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com